

रेल समाचार ब्यूरो

सन् 1990 से रेल सेवा में समर्पित

“सभी पाठकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं! रंगों का पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई उमंग लेकर आए।”



“भारतीय रेल की सभी महिला कर्मचारियों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! आपकी समर्पण भावना, मेहनत और साहस देश की प्रगति को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं”

वर्ष-36 अंक:05 रेल समाचार ब्यूरो प्रयागराज 01-16 मार्च 2026 पृष्ठ 12, (सयुक्तांक) मूल्य:20 रु. मात्र डाक खर्च (रंगीन सहित)



नवाचार को रफ्तार देने और दावा प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए 'रेल टेक पोर्टल' लॉन्च

कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई मजबूत प्रौद्योगिकीय विचार हैं, वह समर्पित रेल टेक पोर्टल के माध्यम से रेलवे से संपर्क कर सकता है, जिससे रेलवे में प्रौद्योगिकी का व्यापक और प्रणालीगत समावेश हो सके

सूत्र/रे.स.ब्यू- रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने प्रौद्योगिकी-संचालित शासन और नवाचार-आधारित परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज भारतीय रेल की प्रमुख “52 सप्ताह में 52 सुधार” पहल के तहत सुधार संख्या तीन और सुधार संख्या चार के रूप में रेल टेक नीति और रेल दावा न्यायाधिकरण (आरसीटी) के पूर्ण डिजिटलीकरण की घोषणा की। रेल प्रौद्योगिकी नीति का उद्देश्य भारतीय रेल में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स, उद्योग और संस्थानों को शामिल करना है। नई नीति नवप्रवर्तकों के चयन को सरल बनाती है और नवोन्मेषण के

लिए एक समर्पित “रेल प्रौद्योगिकी पोर्टल” की शुरुआत करती है। कोई भी नवप्रवर्तक या विभागीय उपयोगकर्ता प्रस्तावों को एकल-चरण में विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने के माध्यम से नवाचार चुनौतियों की शुरुआत कर सकता है। इस नीति में उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान किया गया है, विस्तार अनुदान को तीन गुना से अधिक बढ़ाया गया है और प्रोटोटाइप विकास तथा परीक्षणों के लिए अधिकतम अनुदान को दोगुना कर दिया गया है।

प्रमुख नवोन्मेषण क्षेत्रों में एआई-आधारित एलीफेंट इंटरजन डिटेक्शन सिस्टम (ईआईडीएस), कोचों में एआई-आधारित फायर डिटेक्शन

सिस्टम, ड्रोन-आधारित ब्रोकेन रेल डिटेक्शन सिस्टम, रेल स्ट्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्सल वैन (वीपीयू) पर सेंसर-आधारित लोड कैलकुलेशन डिवाइस, कोचों पर सौर पैनल, एआई-आधारित कोच सफाई निगरानी प्रणाली, कोहरे वाले मौसम में बाधा पहचान और एआई-आधारित पेंशन और विवाद समाधान प्रणाली शामिल हैं।

श्री वैष्णव ने तीसरे सुधार की रूपरेखा बताते हुए कहा कि रेल प्रौद्योगिकी नीति का उद्देश्य रेलवे में प्रौद्योगिकी का व्यापक और व्यवस्थित समावेश करना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों को निश्चित रूप से भारतीय रेल से एक संरचित, सार्थक और सरल तरीके से जुड़ना चाहिए।

ई-आरसीटी : 'रेल दावा न्यायाधिकरण' मामलों के निपटान में सुधार

श्री वैष्णव ने सुधार संख्या चार में रेल दावा न्यायाधिकरण (आरसीटी) के पूर्ण डिजिटलीकरण और एआई-सक्षम रूपांतरण की घोषणा की। ई-आरसीटी प्रणाली रेलवे दावा न्यायाधिकरण के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण को सक्षम बनाएगी। यह दावों को दाखिल करने, संसाधित करने और उनका निपटारा करने की प्रक्रिया को तेज, अधिक पारदर्शी और देश में कहीं से भी सुलभ बनाकर उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।

श्री वैष्णव ने कहा कि देशभर में 23 आरसीटी बेंच हैं और वर्तमान में दावे दाखिल करना चुनौतीपूर्ण है, खासकर उन यात्रियों के लिए जो किसी घटना के समय राज्यों के बीच यात्रा कर रहे हों। दावा दाखिल करने के लिए उपयुक्त क्षेत्राधिकार का निर्धारण अक्सर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है।

उन्होंने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य दावा दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और देश में कहीं से भी सुलभ बनाना है। नई प्रणाली के तहत, पीड़ित यात्री किसी भी स्थान से यात्रा के दौरान या अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा दाखिल कर सकेंगे। ई-फाइलिंग से लेकर केस सूचना प्रणाली तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज किया जाएगा और एआई सक्षम बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि अगले 12 महीनों के भीतर, इस पहल के तहत रेलवे दावा न्यायाधिकरण की सभी बेंचें पूरी तरह से डिजिटलाइज हो जाएंगी।

उन्होंने संकेत दिया कि यदि यह मॉडल सफल साबित होता है, तो इसी तरह के डिजिटल समाधानों को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जैसे अन्य न्यायाधिकरणों तक भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य त्वरित प्रक्रिया, बेहतर पारदर्शिता और न्याय वितरण के लिए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।

वास्तविक फाइलिंग से लेकर डिजिटल एक्सेस तक

पहले, याचिकाकर्ताओं और अधिवक्ताओं को मामले दर्ज करने, दस्तावेज जमा करने और मामले की प्रगति पर नजर रखने के लिए ट्रिब्यूनल कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता था, जिसमें यात्रा, समय और प्रक्रियात्मक विलंब शामिल थे। ई-आरसीटी प्रणाली की शुरुआत के साथ, अब कहीं से भी, कभी भी ऑनलाइन मामले दर्ज किए जा सकते हैं, जिससे मुकदमेबाजों के लिए पहुंच, सुविधा और पारदर्शिता में अत्यधिक सुधार हुआ है।

रेल दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित रेलवे दावा न्यायाधिकरण, रेल दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में मृत्यु या चोट के मुआवजे, माल की हानि या गैर-वितरण और किराए और भाड़े की वापसी से संबंधित रेलवे प्रशासन के खिलाफ दावों का निपटारा करता है। वर्तमान में, आरसीटी भारत के 21 शहरों में स्थित 23 बेंचों के माध्यम से कार्य करता है, जिसका प्रधान बेंच दिल्ली में है। प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होते हैं।

पेपरलेस न्यायालयों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म

ई-आरसीटी सिस्टम सभी 23 बेंचों को एक ही प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से कनेक्ट करेगा और निम्नलिखित को सक्षम करेगा:

- कागजी कार्यवाई रहित न्यायालय का संचालन
- डिजिटलाइज्ड केस जीवन-चक्र
- ऑनलाइन माध्यम से याचिकाओं और नोटिस का आदान-प्रदान
- दैनिक आदेश और निर्णय की ऑनलाइन घोषणा
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में हाइब्रिड सुनवाई (वास्तविक वर्युअल माध्यम) आयोजित की जाएगी।

इस प्रणाली में सभी आरसीटी बेंचों के लिए एक संशोधित गतिशील माइक्रोसाइट भी शामिल है, जो पारदर्शिता और सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा देता है।



ई-आरसीटी के प्रमुख मॉड्यूल

इस प्लेटफॉर्म में तीन मुख्य घटक शामिल हैं:

1. ई-फाइलिंग

- किसी भी स्थान से चौबीसों घंटे सातों दिन ऑनलाइन दावे और कानूनी दस्तावेज दाखिल करने की सुविधा।
- याचिकाओं, हलफनामों, अनुलग्नकों और सहायक दस्तावेजों को अपलोड करना
- एसएमएस और ईमेल अलर्ट के माध्यम से तत्काल पुष्टि
- ऑनलाइन जांच, दोष सूचना और पुनः दाखिल करना

2. केस सूचना प्रणाली (सीआईएस)

- सभी मामलों का केंद्रीकृत डेटाबेस
- स्वतः आवंटन और केस पंजीकरण
- आवेदन दाखिल करने से लेकर अंतिम निपटान तक वास्तविक समय में ट्रैकिंग
- समय-निर्धारण, सुनवाई प्रबंधन और प्रगति की निगरानी

3. दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस)

- अभिवेदनों, सूचनाओं, समनो, आदेशों और निर्णयों का डिजिटल भंडारण
- डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित रिकॉर्ड
- केस फाइलों और आदेशों को आसानी से प्राप्त करना
- आपदा से उबरने की क्षमता के साथ सुरक्षित और विश्वसनीय रिकॉर्ड प्रबंधन

हाइब्रिड ई-सुनवाई और स्वचालित केस प्रवाह

यह प्रणाली ऑनलाइन सुनवाई, डिजिटल साक्ष्य रिकॉर्डिंग, पक्षों के साथ इलेक्ट्रॉनिक संचार, स्वचालित अलर्ट और ऑनलाइन अनुपालन ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप कम होता है और दक्षता में सुधार होता है।

न्याय का त्वरित, पारदर्शी और लोक-हितैषी वितरण

ई-आरसीटी प्रणाली से कई लाभ प्राप्त होंगे:

- तत्काल पंजीकरण और स्वचालित कार्यप्रवाह के माध्यम से मामलों की प्रोसेसिंग में तेजी।
- सुनवाई स्थिति होने की संख्या में कमी आई है, क्योंकि पक्षकार यात्रा संबंधी बाधाओं के बिना ऑनलाइन सुनवाई में भाग ले सकते हैं।
- डिजिटल सूचनाओं के माध्यम से वास्तविक समय में केस की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।
- आदेशों और निर्णयों तक ऑनलाइन पहुंच, जिससे प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में होने वाली देरी खत्म हुई है।
- यात्रा, छपाई और कूरियर खर्चों में कटौती करके लागत में बचत
- सुरक्षित डिजिटल स्टोरेज के साथ बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन
- लंबित मामलों, केस के रुझान और निपटान से संबंधित केंद्रीकृत रीयल-टाइम डेटा

भोपाल से धनबाद और चोपन के लिए सीधी कनेक्टिविटी केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने एक्सप्रेस ट्रेनों को किया खाना

नई रेल सेवाओं से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और झारखंड तक व्यापार और यात्री संपर्क और मजबूत होगा

सूत्र/रे.स.व्यू- रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्थित रेल भवन से वर्चुअल माध्यम के जरिए ट्रेन संख्या 11631/32 भोपाल-धनबाद-भोपाल नई त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 11633/34 भोपाल-चोपन-भोपाल नई साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर खाना किया। यह मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में रेल संपर्क और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस परियोजना का शुभारंभ समारोह भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा और श्री राजेंद्र शुक्ला, संसद सदस्य श्री आलोक शर्मा और डॉ. राजेश मिश्रा, विधानसभा सदस्य श्रीमती राधा सिंह और श्रीमती रीति पाठक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित किया गया।

रेल यात्रियों की सुविधा और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए सीधे संपर्क की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए ये नई रेल सेवाएं शुरू की गई हैं।

श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में रेल विकास अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है।



उन्होंने बताया कि इस दौरान मध्य प्रदेश से सीधे जुड़ने वाली लगभग 48,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

श्री वैष्णव ने कहा कि क्षेत्र के लिए एक बहुप्रतीक्षित परियोजना, इंदौर-मनमाड़ नई रेलवे लाइन को 18,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई है। भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना को 3,500 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है, जबकि प्रयागराज-मानिकपुर तीसरी लाइन परियोजना को 1,640 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है। रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना को 1,000 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, इटारसी-नागपुर चौथी रेलवे लाइन परियोजना को 5,400 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। महत्वपूर्ण इटारसी-भोपाल-बीना चौथी लाइन कॉरिडोर, जो एक बेहद व्यस्त मार्ग है, उसे 4,300 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है। वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन परियोजना को 8,800 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 5,200 करोड़ रुपए की लागत से गोंडिया-जबलपुर दोहरीकरण परियोजना को भी मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा जारी अन्य प्रमुख परियोजनाओं में रामगंज मंडी-भोपाल, ललितपुर-सिंगरौली, इंदौर-बुधनी, बीना-कटनी तीसरी लाइन, सतना-रीवा और कटनी-सिंगरौली दोहरीकरण, कटनी ग्रेड सेपरेटर और गेज रूपांतरण परियोजनाएं शामिल हैं, जिनसे रेल क्षमता, समयबद्धता और माल ढुलाई में उल्लेखनीय सुधार होगा। माल ढुलाई और रसद दक्षता बढ़ाने के लिए, केंद्रीय बजट में पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे का प्रस्ताव रखा गया है, जो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह नया माल ढुलाई गलियारा मध्य प्रदेश के बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास के लिए एक मजबूत आधार बनेगा। 2,052 किलोमीटर लंबा यह पूर्व-पश्चिम गलियारा, मौजूदा पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे से जुड़ेगा, जिससे पश्चिमी बंदरगाहों तक माल की निर्बाध आवाजाही बेहतर हो पाएगी, मौजूदा रेल नेटवर्क पर दबाव कम होगा और औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर के जरिए मध्य प्रदेश पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों से बेहतर ढंग से जुड़ पाएगा, जिनमें गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाह भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में बन रहा वधवन बंदरगाह, जिसके पूरा होने पर दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होने की उम्मीद है, और हजीरा और मुंद्रा जैसे मौजूदा बंदरगाह भी साथ मिलकर राज्य की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे।

इन बंदरगाहों से उच्च गति के माल ढुलाई संपर्क के साथ, मध्य प्रदेश के उद्योगों को कंटेनरीकृत कार्गो या थोक वस्तुओं के निर्यात और आयात दोनों कार्यों में काफी लाभ होगा। इस बेहतर लॉजिस्टिक्स प्रणाली से राज्य में औद्योगिक विकास में तेजी आने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नवनिर्मित रेल सेवा के शुरू होने पर प्रसन्नता जताई, जिससे सिंगरौली को प्रतिदिन रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्होंने इस विकास को क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार बताया। उन्होंने श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया और कहा कि सिंगरौली के अलावा, यह ट्रेन सिंगरौली और धनबाद के बीच यात्रा करने वाले लोगों को भी लाभ पहुंचाएगी, जहां कई निवासी व्यापार, व्यवसाय और रोजगार के जरिए जुड़े हुए हैं। डॉ. यादव ने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से झारखंड और बिहार के साथ सीधा रेल संपर्क स्थापित हो गया है, जिससे तीनों राज्यों के निवासियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह नई रेल सेवा केवल एक परिवहन सुविधा

भोपाल-धनबाद-भोपाल नई त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 11631/32)

यह ट्रेन भोपाल और धनबाद के बीच कुल 30 स्टेशनों पर रुकेगी। नियमित सेवा के तहत, यह भोपाल से 20:55 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 20:30 बजे धनबाद पहुंचेगी। वापसी में, यह धनबाद से 07:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:00 बजे भोपाल पहुंचेगी। इस ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल क्लास के कुल 24 कोच होंगे।

भोपाल-चोपन-भोपाल नई साप्ताहिक एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 11633/34)

यह ट्रेन भोपाल और चोपन के बीच 15 स्टेशनों पर रुकेगी। नियमित सेवा के तहत, यह भोपाल से रात 8:55 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 10:50 बजे चोपन पहुंचेगी। वापसी में, यह चोपन से शाम 17:10 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 7:00 बजे भोपाल पहुंचेगी। इस ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल क्लास के कोचों सहित कुल 24 कोच होंगे।

नई ट्रेन सेवाओं के लाभ

नई ट्रेन सेवाओं से विदिशा, गंज बसोदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुरवारा, खन्ना बंजारी, ब्योहरी, सिंगरौली, चोपन, चंद्रपुरा और धनबाद आदि के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

ये ट्रेनें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच संपर्क को मजबूत करेंगी और सिंगरौली कोयला क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों को राजधानी भोपाल से जोड़ेंगी। इन सेवाओं से तीनों राज्यों में व्यापार, ऊर्जा और खनन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

यात्रियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और भरोसेमंद रेल सेवाओं का लाभ मिलेगा, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। नई ट्रेनें पर्यटन, स्थानीय व्यापार, उद्योग और शिक्षा को भी बढ़ावा देंगी और दैनिक यात्रियों और आने-जाने वाले यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करेंगी।

इन ट्रेनों का शुभारंभ सरकार की रेल अवसंरचना को मजबूत करने, यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और क्षेत्रों के बीच निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मध्य प्रदेश में रेल विकास

भारत का हृदय कहलाने वाला मध्य प्रदेश, इस विकास यात्रा में अहम भूमिका निभा रहा है। राज्य में रेल संपर्क का विस्तार, नई लाइनों का निर्माण और बुनियादी ढांचे का मजबूत होता व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं, जिससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि देश की समग्र प्रगति में भी योगदान मिल रहा है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के रूप में 2,93,030 करोड़ रुपए और सुरक्षा के लिए रिकॉर्ड 1.20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी क्रम में, मध्य प्रदेश को रेलवे विकास के लिए 15,188 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जो 2009-2014 की अवधि की तुलना में 24 गुना अधिक है। यह रिकॉर्ड आवंटन मध्य प्रदेश में रेलवे अवसंरचना, सुरक्षा, यात्री सुविधाओं और माल ढुलाई क्षमता को नई रफ्तार देगा।

वर्तमान में, राज्य में 1,18,379 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही हैं और मध्य प्रदेश में रेलवे लाइनों का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 80 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से कुछ का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 2025 में किया जा चुका है।

सुरक्षा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में 4,591 किलोमीटर मार्ग पर कवच प्रणाली लागू करने की योजना तैयार की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए, राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस की 5 जोड़ी और अमृत भारत एक्सप्रेस की 4 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस वर्ष अतिरिक्त वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस और नई ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी।



श्री वी. सोमन्ना ने “कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन, एक हजार तीर्थों की यात्रा” नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया

यह पुस्तक भारतीय रेलवे की सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन पहलों में से एक समर्पित समृद्ध दृश्य और कथात्मक श्रद्धांजलि है : श्री वी सोमन्ना

सूत्र/रे.स.ब्यू. केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने 23 फरवरी 2026 को रेल भवन में “कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन: एक हजार तीर्थों की यात्रा” नामक क फी टेबल बुक का विमोचन किया। श्री सोमन्ना ने कहा कि यह पुस्तक भारतीय रेलवे की सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन पहलों में से एक समृद्ध दृश्य और कथात्मक श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि पुस्तक उस अग्रणी मॉडल के पीछे की भावना, दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयास को खूबसूरती से दर्शाती है जो आस्था, संस्कृति, विरासत और आधुनिक रेल अवसंरचना को सहजता से एकीकृत करता है। इस उल्लेखनीय पहल की परिकल्पना और संचालन डॉ. अनुप दयानंद, आईआरटीएस (सेवानिवृत्त) द्वारा किया गया था।

श्री सोमन्ना ने कहा कि यह ऐतिहासिक है कि भारत गौरव योजना के तहत कर्नाटक के 30 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किफायती लागत पर काशी और अन्य पवित्र स्थलों की यात्रा करने के अपने जीवन भर के सपने को पूरा किया है।

यह पुस्तक ट्रेन को “भारत की चलती-फिरती गैलरी” के रूप में जीवंत रूप से प्रस्तुत करती है, जिसमें इसके सुविचारित डिब्बों, ट्रेन में उपलब्ध सुविधाओं, सुनियोजित आध्यात्मिक यात्राओं और यात्रियों के संपूर्ण अनुभव का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि कैसे आराम, सुगमता और वहनीयता को प्राथमिकता दी गई, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और पहली बार तीर्थयात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नीतिगत समर्थन और राज्य सब्सिडी के माध्यम से। मूल रूप से, यह पुस्तक भारत गौरव नीति के तहत कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन की परिकल्पना, विकास और सफल कार्यान्वयन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है।

कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन

कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन भारतीय रेलवे की भारत गौरव नीति के अंतर्गत एक प्रमुख तीर्थयात्रा पर्यटन पहल का प्रतिनिधित्व करती



है। यह रेलवे को केवल परिवहन साधन से बदलकर पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्मिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्थापित करती है। यह पहल “देखो अपना देश” और “एक भारत श्रेष्ठ भारत” जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप है, जो साझा आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। काशी दर्शन, ज्योतिर्लिंग दर्शन, शक्ति पीठ यात्रा, दक्षिण यात्रा, द्वारका यात्रा और पुरी जगन्नाथ यात्रा जैसी थीम आधारित यात्राओं के माध्यम से, यह ट्रेन कर्नाटक के तीर्थयात्रियों को भारत भर के प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों से जोड़ती है। सर्व-समावेशी पैकेजों में रेल यात्रा, शाकाहारी भोजन, आवास, स्थानीय परिवहन, टूर गाइड और दर्शनीय स्थल शामिल हैं, जो एक सहज और गरिमापूर्ण अनुभव सुनिश्चित करते हैं।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 46 यात्राएं सफलतापूर्वक संचालित की गई हैं जिनमें 28,786 तीर्थयात्रियों ने यात्रा की है, जिससे भारतीय रेलवे को लगभग 25.57 करोड़ रुपये की आय हुई है और साथ ही समावेशी तीर्थयात्रा पर्यटन के व्यापक उद्देश्य को आगे बढ़ाया गया है।

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए वातानुकूलित लोकल सेवाओं में वृद्धि

कार्यदिवसों में 133 एवं सप्ताहांत में 106 वातानुकूलित लोकल सेवाएं सप्ताहांत में यात्रियों के लिए सफर हुआ और भी आसान

सूत्र/रे.स.ब्यू. पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम रेलवे पर वातानुकूलित (एसी) लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यात्रियों की बढ़ती लोकप्रियता और मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे मुंबई उपनगरीय खंड में वातानुकूलित लोकल सेवाओं की संख्या निरंतर बढ़ा रही है।



वर्तमान में पश्चिम रेलवे द्वारा अपने उपनगरीय नेटवर्क पर सोमवार से शुक्रवार 133 एसी लोकल सेवाएं संचालित की जा रही है। वहीं शनिवार और रविवार को 106 एसी लोकल सेवाएं चलाई जा रही हैं, जिससे सप्ताहांत में यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा और आराम मिल रहा है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस वर्ष कई नई लोकल सेवाएं शुरू की गई हैं, जिनमें एसी सेवाएं भी शामिल हैं। जनवरी माह में 12 एसी लोकल सेवाएं शुरू की गईं तथा फरवरी में 12 और सेवाएं जोड़ी गईं। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे पर एसी सेवाओं की कुल संख्या बढ़कर 133 हो गई है। एसी सेवाओं की बढ़ी हुई संख्या से यात्रियों को सप्ताहांत में भी सुविधाजनक, आरामदायक और वातानुकूलित यात्रा का अनुभव मिल रहा है। एसी लोकल ट्रेनें बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करती हैं और उपनगरीय नेटवर्क के विभिन्न वर्गों के यात्रियों से इन्हे लगातार सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। सप्ताहांत पर अतिरिक्त एसी सेवाओं की उपलब्धता से विशेष रूप से उन यात्रियों को लाभ हुआ है जो कार्यालय, अवकाश या अन्य व्यक्तिगत कार्यों के लिए यात्रा करते हैं। साथ ही, इससे आगामी ग्रीष्म ऋतु में भी यह यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। पश्चिम रेलवे सुरक्षित, कुशल और यात्री-अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एसी लोकल सेवाओं की बढ़ी हुई उपलब्धता दैनिक यात्रा की गुणवत्ता में सुधार करने और मुंबई की जीवनरेखा को और सुदृढ़ बनाने के इसके निरंतर प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यात्री सुविधाओं को गति: टर्मिनल विस्तार के निर्देश, 76 स्टेशनों पर कार्य की समीक्षा

सूत्र/रे.स.ब्यू. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देशभर के प्रमुख यात्री ट्रेन टर्मिनलों की क्षमता बढ़ाने की योजना की समीक्षा की और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों और संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। भारतीय रेलवे महानगरों में भीड़ कम करने, ट्रेन संचालन को सुचारु बनाने और यात्रियों की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए टर्मिनल की संचालन क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ा रहा है और कुछ प्रमुख स्थानों पर इसे दोगुना कर रहा है। क्षमता वृद्धि में प्लेटफार्मों, आवागमन क्षेत्रों, प्रवेश-निकास बिंदुओं, यात्री सुविधाओं का विस्तार और यातायात प्रवाह प्रबंधन में सुधार शामिल है। मंत्री महोदय ने देशभर के 76 रेलवे स्टेशनों पर

विकसित किए जा रहे प्रतीक्षा क्षेत्रों की प्रगति की भी समीक्षा की। इन प्रतीक्षा क्षेत्रों का उद्देश्य विशेष रूप से त्योहारों और व्यस्त यात्रा अवधियों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। भीड़ के प्रवाह को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करने, सुरक्षा बढ़ाने और स्टेशन परिसर के अंदर भीड़भाड़ को रोकने के लिए ये प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कार्यों को समय पर पूरा करने और कड़ी निगरानी पर जोर दिया।

ये उपाय विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप हैं, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुनियोजित परिवहन केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनमें कुशल यात्री प्रबंधन प्रणाली और उन्नत बुनियादी ढांचा मौजूद है।

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त श्री जनक कुमार गर्ग का बरेका में निरीक्षण, आधुनिक तकनीक व संरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायज़ा



सूत्र/रे.स.ब्यू. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, नई दिल्ली श्री जनक कुमार गर्ग ने दिनांक 20 फरवरी 2026 को बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) का विस्तृत निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने बरेका में निर्मित लोको (रेल इंजनों), उनकी उन्नत निर्माण प्रक्रिया, गुणवत्ता मानकों तथा संरक्षा उपायों का गहन अवलोकन किया।

कार्यशाला पहुंचने पर मुख्य विद्युत इंजीनियर श्री अरविंद कुमार जैन ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इसके पश्चात उन्होंने लोको फ्रेम शॉप, लोको असेंबली शॉप, ट्रक मशीन शॉप एवं लोको टेस्ट शॉप का निरीक्षण कर निर्माण प्रक्रिया की गुणवत्ता एवं संरक्षा मानकों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर श्री

सुशील कुमार श्रीवास्तव ने बरेका में निर्मित विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों, उनकी अत्याधुनिक निर्माण तकनीक, उच्च गुणवत्ता मानकों एवं संरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री विवेक शील, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक श्री आलोक अग्रवाल, प्रधान वित्त सलाहकार श्री मुक्तेश मित्तल, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री लालजी चौधरी, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के इस दौरे का उद्देश्य बरेका में निर्मित रेल इंजनों की उन्नत निर्माण प्रणाली, गुणवत्ता नियंत्रण तथा संरक्षा व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर रेलवे संरक्षा मानकों को और सुदृढ़ करना रहा।

RailOne सुपरऐप ने लॉन्च होने के 8 महीने से भी कम समय में 2 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार किया

सूत्र/रे.स.ब्यू. भारतीय रेलवे के सुपरऐप, रेल वन ने लॉन्च होने के 8 महीने से भी कम समय में 2 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इस महीने प्रतिदिन 5 लाख टिकटों का आंकड़ा भी पार कर लिया है। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) द्वारा विकसित इस ऐप को माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किया था।

तब से, देश भर के रेल यात्रियों के बीच इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। रेल वन ऐप एक एकीकृत डिजिटल गेटवे के रूप में उभर रहा है, जो एक ही सहज इंटरफेस के माध्यम से यात्रियों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है। अपनी परिचालन क्षमता और विश्वसनीयता को दर्शाते हुए, रेल वन अब प्रतिदिन लगभग 6 लाख टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है, जो इसकी मजबूती और बढ़ते उपयोगकर्ता विश्वास को रेखांकित करता है। यह ऐप आरक्षित टिकट बुकिंग, अनारक्षित टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन पूछताछ, पीएनआर स्थिति



विश्वास को दर्शाता है रेल वन आरक्षित, अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग के साथ-साथ पीएनआर और ट्रेन पूछताछ सेवाओं को एक ही सहज प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है।

और अन्य यात्री-केंद्रित सुविधाओं सहित प्रमुख रेलवे सेवाओं को एकीकृत करता है। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे के डिजिटल परिवर्तन और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। अपनी स्केलेबल संरचना, सहज डिजाइन और उपयोगकर्ता अनुभव पर केंद्रित होने के कारण, रेल वन रेलवे सेवाओं के साथ नागरिकों के जुड़ाव के तरीके को नया रूप दे रहा है। रेल वन नए फीचर्स और ए आई-संचालित क्षमताओं के साथ लगातार विकसित हो रहा है, जो भारत के लिए एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी-सक्षम रेलवे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। रेल वन प्रतिदिन लगभग 6 लाख टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है, जो इसकी व्यापकता, विश्वसनीयता और बढ़ते उपयोगकर्ता विश्वास को दर्शाता है रेल वन आरक्षित, अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग के साथ-साथ पीएनआर और ट्रेन पूछताछ सेवाओं को एक ही सहज प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है।

रेलवन ऐप से अनारक्षित रेल टिकट पर सभी डिजिटल पेमेंट मोड से मिलेगा 3% का लाभ

भारतीय रेलवे यात्रियों को डिजिटल माध्यमों से अधिक सुविधा, पारदर्शिता एवं प्रोत्साहन देने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मंडल रेल प्रबंधक आगरा श्री गगन गोयल के मार्गदर्शन व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अंकित गुप्ता के निर्देशन में दिनांक 26.02.2026 को आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को रेल वन ऐप के बारे में बताया गया एवं यात्रियों को यह ऐप कैसे उपयोग किया जाता है वह प्रॉपर करके दिखाया भी गया, यात्री काफी संतुष्ट हुए और कुछ यात्रियों द्वारा ऐप को डाउनलोड भी किया गया, यात्रियों द्वारा बताया गया कि यह ऐप बहुत अच्छा है, एक ही ऐप के अंदर सब कुछ है। रेलवे द्वारा संचालित रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित रेल टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं लाभकारी सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। इसे प्रायोगिक स्तर पर 14.01.2026 से 14.07.2026 तक लागू किया जा रहा है।

अब तक रेलवन ऐप पर अनारक्षित टिकट बुक करते समय केवल आर-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने पर ही यात्रियों को 3 प्रतिशत बोनस कैशबैक की सुविधा मिलती थी। यात्रियों की सुविधा एवं डिजिटल भुगतान को और अधिक लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से रेलवे ने इस लाभ को अब सभी डिजिटल पेमेंट मोड पर लागू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब रेलवन ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट लेते समय यदि यात्री यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग अथवा अन्य स्वीकृत डिजिटल भुगतान माध्यमों का उपयोग करते हैं, तो उन्हें भी टिकट मूल्य पर 3 प्रतिशत की छूट प्रपट होगी जिससे यात्रियों को टिकट बुकिंग में सीधी बचत होगी। रेलवे का यह कदम यात्रियों को कैशलेस लेन-देन के लिए प्रेरित करने के साथ डिजिटल इंडिया अभियान को और मजबूती प्रदान करेगा। विशेष रूप से दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों, उपनगरीय क्षेत्रों के यात्रियों एवं अनारक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले आम नागरिकों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। एकीकृत सुपर ऐप के रूप में CRIS द्वारा विकसित रेलवन ऐप का बीटा संस्करण जनवरी 2025 में शुरू किया गया था। इसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड कर रेल कनेक्ट या यूटीएस मोबाइल ऐप के मौजूदा उपयोगकर्ता अपने पहचान के प्रमाण के साथ सीधे लॉग इन कर सकते हैं। रेलवन ऐप पर अनारक्षित टिकट, आरक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन एवं स्टेशन से जुड़ी विभिन्न जानकारी, शिकायत निवारण एवं अन्य यात्री सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हैं। अनारक्षित टिकट के लिए काउंटर पर लगने वाली लंबी कतारों से बचने में यह ऐप पहले से ही यात्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अब सभी डिजिटल भुगतान मोड पर 3% लाभ की सुविधा मिलने से इसकी लोकप्रियता में और वृद्धि होने की संभावना है। यह पहल न केवल यात्रियों के समय एवं धन की बचत करेगी, बल्कि रेलवे की सेवाओं को और अधिक आधुनिक, सुगम एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी।

भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के करियर के अवसरों को और बेहतर बनाने के लिए 'सहयोग का ढांचा' शुरू किया

सूत्र/रे.स.ब्यू. संस्थागत सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने "सहयोग ढांचा" शुरू किया है। इसका मकसद अग्निवीरों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है, जो बतौर आम नागरिक वे बेहतर जीवन बिता सकें।

सेना और रेल मंत्रालय के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य सैन्य से नागरिक करियर में सरल बदलाव सुनिश्चित करना है। इससे रेलवे में रोजगार की संभावनाओं के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी और सेवानिवृत्त कर्मियों की सहायता के लिए एक समर्पित सहायता प्रणाली भी तैयार होगी।

यह सहयोगात्मक ढांचा पूर्व सैनिकों को सार्थक दूसरा करियर मार्ग प्रदान करने और व्यापक राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों का समर्थन करने की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के प्रमुख अवसर

सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों का कल्याण और पुनर्वास, भारतीय रेलवे की नीतिगत संरचना का एक जरूरी घटक है।

पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु:

- स्तर-2/उससे ऊपर के पदों में 10% और स्तर-1 के पदों में 20% क्षेतिज आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित किया गया है।
- इसके अलावा, स्तर-2/उससे ऊपर के पदों में 5% और स्तर-1 के पदों में 10% आरक्षण पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया गया है।
- वर्ष 2024 और 2025 में, रेलवे की रिक्तियों की अधिसूचनाओं में पूर्व सैनिकों के लिए कुल 14,788 पद आरक्षित किए गए थे, जिनमें शामिल हैं:
 - स्तर-1 में 6,485 पद
 - स्तर-2/ऊपर के पदों में 8,303 पद



स्तर-1 (पूर्ववर्ती ग्रुप डी) और स्तर-2/ऊपर के पदों पर भर्ती क्रमशः रेलवे भर्ती केंद्रों (आरआरसी) और रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाती है।

सविदात्मक नियुक्तियों के जरिए तत्काल भर्ती

पूर्व सैनिकों की त्वरित भर्ती को बढ़ावा देने और रिक्त पदों को भरने के लिए, रेल मंत्रालय ने नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक भारतीय रेलवे में

संविदा आधार पर पूर्व सैनिकों को 'पॉइंट्समैन' के रूप में भर्ती करने का फैसला किया है।

वर्तमान में जोनल और मंडल स्तर पर 5,000 से अधिक लेवल-1 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अब तक, 9 मंडलों ने पॉइंट्समैन की भर्ती के लिए संबंधित सेना संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सहयोगात्मक ढांचा, सेना भर्ती संगठनों से रेलवे मंडलों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर इन पदों को शीघ्रता से भरने का आह्वान करता है।

राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक शक्तियों का उपयोग

भारतीय रेलवे और भारतीय सेना सेवाकाल के दौरान विकसित बहुमूल्य कौशल, अनुशासन, तकनीकी दक्षता और नेतृत्व गुणों को साझा करते हैं, जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बड़ी संख्या में सैनिक अपेक्षाओं कम उम्र में ही समृद्ध परिचालन और प्रबंधकीय अनुभव, दृढ़ अनुशासन और राष्ट्रवाद की भावना के साथ सेवानिवृत्त होते हैं।

भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बीच सहयोग रसद और कर्मियों की आवाजाही में अहम भूमिका निभाता है। समर्पित माल गलियारों और उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक जैसी रणनीतिक परियोजनाओं ने सैनिकों और उपकरणों की त्वरित तैनाती क्षमताओं को बढ़ाया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के जरिए कोशल साझाकरण पहलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

यह ढांचा मौजूदा भर्ती प्रणाली के भीतर ही पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों की सुनियोजित भागीदारी को बढ़ावा देता है और दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत करता है। यह पहल राष्ट्रीय अवसररचना और सुरक्षा समन्वय को मजबूत करते हुए सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के अनुभव और अनुशासन का लाभ उठाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा कलानौर कलां - डोभभाली दोहरीकृत रेलखंड का निरीक्षण



सूत्र/रे.स.ब्यू. उत्तर पश्चिम रेलवे पर बीकानेर मंडल के कलानौर कलां - डोभभाली रेलखंड के दोहरीकरण कार्य का दिनांक 24.02.2026 को रेल संरक्षा आयुक्त (पश्चिम परिमंडल) ई. श्रीनिवासन द्वारा विस्तृत निरीक्षण किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री अमित सुदर्शन के अनुसार रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा बीकानेर रेल मंडल के कलानौर कलां - डोभभाली रेलखंड के दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ट्रैक के ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, वेल्डिंग गुणवत्ता, बेलास्ट पैकिंग, स्लीपर फिटमेंट, ओवरहेड (ओवरहेड इलेक्ट्रिकीफिकेशन) की स्थिति तथा सिग्नलिंग प्रणाली की कार्यक्षमता का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त समपार फाटकों, पुल-पुलियों, यार्ड लेआउट तथा यात्री सुविधाओं का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान रेल संरक्षा आयुक्त ने मोटर ट्रॉली निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों पर ट्रैक का भी निरीक्षण किया गया।

रेल संरक्षा आयुक्त श्री ई. श्रीनिवासन ने निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी नए अथवा उन्नत रेलखंड को यात्री सेवा के

लिए स्वीकृति देने से पूर्व व्यापक परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमित निरीक्षण, ट्रैक मंटेनेंस और सिग्नलिंग मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दी जाए। निरीक्षण के अंतर्गत कलानौर स्टेशन का भी विस्तृत अवलोकन किया गया। स्टेशन यार्ड की संरचना, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, यात्री प्रतीक्षालय, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, टिकट काउंटर तथा सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया गया। रेल संरक्षा आयुक्त ने स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं की सलाहना करते हुए आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव भी दिए। दोहरीकरण कार्य के अंतर्गत अत्याधुनिक मशीनों और तकनीकों का उपयोग किया गया। हाई-स्पीड ट्रैक लेइंग मशीन, टेम्पिंग मशीन तथा स्वचालित वेल्डिंग तकनीक के माध्यम से ट्रैक को और अधिक मजबूत बनाया गया है। इस रेलखंड के दोहरीकरण से न केवल परिचालन क्षमता बढ़ेगी बल्कि क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। मालगाड़ियों के संचालन में तेजी आएगी, जिससे कृषि उत्पाद, खनिज, औद्योगिक सामग्री तथा अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं की दुलाई अधिक कुशलतापूर्वक हो सकेगी। इससे लाहली स्टेशन के आसपास के लोगों के अतिरिक्त स्थानीय व्यापारियों, किसानों और उद्योगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

डीजल लोको शेड, झाँसी में नवनिर्मित आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन

सूत्र/रे.स.ब्यू. दिनांक 26.02.26 को श्री अनिरुद्ध कुमार, मण्डल रेल प्रबंधक, झाँसी द्वारा डीजल लोको शेड, झाँसी में नवनिर्मित आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा (अपर मण्डल रेल प्रबंधक/इन्फ्रा), श्री नन्दीश शुक्ला (अपर मण्डल रेल प्रबंधक/ऑपरेशन), श्री बी. के. पाण्डेय (मुख्य कारखाना प्रबंधक/सी.एम.एल.आर) एवं श्री सतीश चन्द्र निरंजन (वरि. मण्डल यांत्रिक अभियंता/डीजल) सहित झाँसी मण्डल के अन्य वरिष्ठ एवं शाखा अधिकारी उपस्थित रहे। उद्घाटन के दौरान मण्डल रेल प्रबंधक ने डीजल लोको शेड में किए जा रहे कार्यों की सलाहना की तथा इसे झाँसी मंडल के आधुनिकीकरण एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही लोकोमोटिव की विफलताओं को कम करने की दिशा में प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में झाँसी मंडल के विकास से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के योगदान की प्रशंसा की गई।



बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवॉर्ड्स 2026 में पश्चिम रेलवे दो पुरस्कारों से सम्मानित

सूत्र/रे.स.ब्यू. पश्चिम रेलवे ने बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवॉर्ड्स 2026 में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर गौरव प्राप्त किया है। यह राष्ट्रीय स्तर का मंच है, जो नवाचार, प्रभाव और सतत विकास पर विशेष ध्यान देते हुए अवसररचना विकास में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करता है। पुरस्कार समारोह का आयोजन 24 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल, पॉर्ट्स, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना तथा ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाइक उपस्थित थे। चयन समिति में दूरदर्शी व्यक्तित्व, उद्योग जगत के अग्रणी एवं अनुभवी पेशेवर शामिल थे। विभिन्न श्रेणियों जैसे सड़क, रेल, परिवहन आदि से कुल 146 नामांकन प्राप्त हुए थे।

रेलवे क्षेत्र के लिए यह सम्मान श्री वी. सोमन्ना, रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा प्रदान किया गया, जिसे पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा प्राप्त किया गया। यह पुरस्कार पश्चिम रेलवे की दो महत्वपूर्ण पहलों के लिए प्रदान किए गए गुजरात के दाहोद में भारत का पहला 9000 एचपी विद्युत इंजन निर्माण तथा मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर अत्याधुनिक डिजिटल लाउंज एवं को-वर्किंग स्पेस की स्थापना। ये उपलब्धियां उन्नत प्रौद्योगिकी और यात्री-केंद्रित अवसररचना के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के प्रति पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

निर्माण उत्कृष्टता का पुरस्कार दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में निर्मित देश के पहले 9000 हॉर्सपावर विद्युत इंजन के लिए प्रदान किया गया। यह उच्च क्षमता वाला इंजन भारतीय रेल की माल दुलाई क्षमता और परिचालन दक्षता को



श्री वी. सोमन्ना, रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री, पश्चिम रेलवे को बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवॉर्ड 2026 प्रदान करते हुए, जिसे पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक ने प्राप्त किया।

उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस इंजन का निर्माण हरित ऊर्जा के उपयोग के साथ किया गया है और इसे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग टैग प्रदान किया गया है।

मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर विकसित डिजिटल लाउंज एवं को-वर्किंग स्पेस को यात्री सुविधाओं में नवाचार और गैर-भाड़ा राजस्व सृजन के लिए सम्मानित किया गया। लगभग 1700 वर्ग फुट क्षेत्र में विकसित इस सुविधा को आधुनिक यात्रियों, विशेष रूप से व्यवसायिक पेशेवरों और दूरस्थ कार्य करने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। डिजिटल लाउंज में हाई-स्पीड वाई-फाई, समर्पित बैठक एवं कॉन्फ्रेंस कक्ष तथा वर्चुअल मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध हैं। इसके साथ ही हल्के नाश्ते की

सुविधा भी प्रदान की गई है। यह परियोजना भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और लचीली कार्य संस्कृति के अनुरूप स्टेशन अवसररचना को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवॉर्ड्स ऐसे परिवर्तनकारी अवसररचना परियोजनाओं को सम्मानित करते हैं, जो नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देते हुए सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवॉर्ड्स 2026 में प्राप्त ये दोहरे सम्मान पश्चिम रेलवे की तकनीकी उन्नयन, अवसररचना आधुनिकीकरण और यात्री अनुभव में सुधार की दूरदर्शी सोच को दर्शाते हैं तथा विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हैं।



रेल की हर अपडेट अब आपके मोबाइल पर

बस स्कैन करें यह कोड



रेल समाचार ब्यूरो की वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए अभी स्कैन करें

भारतीय रेल ने अवसंरचना के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए ₹871 करोड़ की विशेष क्षमता और संपर्क परियोजनाओं को मंजूरी दी

एलएचबी और वंदे भारत सेवा को बढ़ावा देने के लिए श्री गंगानगर में ₹174.26 करोड़ की कोच रखरखाव सुविधा और राजस्थान में ₹139.68 करोड़ का संवर्धित लालगढ़ डिपो

केरल में यात्री और माल दुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए तुरावुर-मरारीकुलम खंड को दो लाइन का बनाने के लिए ₹450.59 करोड़

आसनसोल में इंजन रिवर्सल को स्वतंत्र करने और परिचालन दक्षता को बेहतर बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में ₹107.10 करोड़ की कालीपहाड़ी बाईपास लाइन को स्वीकृति

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेल ने भविष्य के लिए तैयार, उच्च क्षमता वाला रेल नेटवर्क बनाने के परिवर्तनकारी प्रयास जारी रखते हुए, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी रेलवे जोन में कई रणनीतिक अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कोचिंग रखरखाव पारिस्थितिकी को आधुनिक बनाना, उच्च घनत्व गलियारों पर भीड़ कम करना, परिचालन रुकावटों को खत्म करना और यात्री एवं माल दुलाई क्षमता को काफी बढ़ाना है।

श्री गंगानगर स्टेशन (फेज-I), उत्तर पूर्वी रेलवे में कोच रखरखाव सुविधा का विकास: ₹174.2644 करोड़

भारतीय रेल ने राजस्थान के श्री गंगानगर स्टेशन पर फेज-I के तहत 174.2644 करोड़ की लागत से कोच रखरखाव सुविधा के विकास को मंजूरी दी है। यह परियोजना एलएचबी और वंदे भारत रेलगाड़ियों सहित आधुनिक रोलिंग स्टॉक के लिए रखरखाव अवसंरचना को उन्नत और विकसित करने की बड़ी पहल का हिस्सा है। अभी, मौजूदा फैसिलिटी वर्तमान परिचालन जरूरतों को पूरा करती हैं, लेकिन आधुनिक रेल और नई सेवा के आने से, बेहतर अवसंरचना जरूरी हो गई है। स्वीकृत कार्यों में 600 मीटर लंबी दो वॉशिंग लाइन, 650-मीटर स्टेबलिंग तीन लाइन, दो पिट लाइन, व्हील लेथ लाइन एक और 650-मीटर इंजन एक्सेप की एक लाइन बनाना शामिल है। 120 मीटर गुणा 24 मीटर का सिक लाइन शेड भी बनाया जाएगा। इसके अलावा, वॉशिंग लाइन के ऊपर कन्वेंशनल ओवर हेड इविएपमेंट (ओएचई) के साथ आधुनिक मशीनरी और प्लांट जैसे सिंक्रोनाइज्ड जैक, फोर्कलिफ्ट, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवेलिंग (ईओटी) क्रेन और ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगाए जाएंगे। शुरू होने पर, इस परियोजना से हर दिन औसत रखरखाव क्षमता में छह और रेल की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इससे परिचालन दक्षता में सुधार होगा, रेल मूवमेंट में आसानी होगी और इस इलाके में और रेल सेवा शुरू करने में मदद मिलेगी।

लालगढ़ (फेज-II), उत्तर पूर्वी रेल में कोचिंग रखरखाव सुविधाओं को बढ़ाना: ₹139.6820 करोड़

बीकानेर इलाके में वंदे भारत और एलएचबी सेवाओं के विस्तार से बढ़ती रखरखाव जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल ने फेज-II के तहत 139.6820 करोड़ की लागत से राजस्थान के लालगढ़ में कोचिंग रखरखाव सुविधाओं को बढ़ाने को मंजूरी दी है। बीकानेर में और विस्तार की कम गुंजाइश को देखते हुए, लालगढ़ को आधुनिक, पूरी तरह से सुसज्जित कोचिंग रखरखाव डिपो के तौर पर विकसित किया जा रहा है जो एडवांस्ड ट्रेनसेट को हैंडल करने में सक्षम है। स्वीकृत कार्यों में 600 मीटर की वॉशिंग लाइन बनाना, चार वॉशिंग लाइनों के ऊपर एक कवर्ड शेड बनाना, सिक लाइन को 120 मीटर गुणा 16 मीटर बढ़ाना, और 1000 वर्ग मीटर की सर्विस बिल्डिंग बनाना शामिल है। इस परियोजना में वॉशिंग लाइन नंबर चार के ऊपर रिट्रैक्टबल ओएचई लगाना, दो सिंक्रोनाइज्ड कोच लिफ्टिंग सिस्टम, दो ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट और दो 25-टन ईओटी क्रेन लगाना भी शामिल है। इस बढ़ोतरी से और वंदे भारत ट्रेनसेट और दूसरे रोलिंग स्टॉक के रखरखाव की तैयारी काफी बेहतर होगी। इससे इस इलाके में बेहतर भरोसा, तेज टर्नअराउंड टाइम और बेहतर यात्री सेवा परिणाम सुनिश्चित होंगे।

तुरावुर-मरारीकुलम डबलिंग (21.10 km), दक्षिणी रेलवे: ₹450.59 करोड़

केरल में क्षमता बढ़ाने की बड़ी पहल में, भारतीय रेल ने दक्षिणी रेलवे के 21.10 किलोमीटर लंबे तुरावुर मरारीकुलम खंड को 450.59 करोड़ की लागत से डबल लाइन करने की मंजूरी दी है। यह खंड रणनीतिक रूप से जरूरी एर्णाकुलम अलपुझा कार्याकुलम गलियारे पर है। यह गलियारा बंदरगाह से जुड़े कार्गो सहित काफी यात्री और माल दुलाई का यातायात संभालता है।



डबलिंग प्रोजेक्ट से हर दिशा में हर दिन नौ और पैसेंजर ट्रेनें चल सकेंगी और हर साल लगभग 2.88 मिलियन टन माल दुलाई बढ़ सकेगी। इससे मालगाड़ियों के रुकने का समय भी 17 से 19 मिनट तक और पैसेंजर ट्रेनों के रुकने का समय लगभग 12 से 15 मिनट तक कम हो जाएगा, जिससे समय की भी काफी बचत होगी। यह खंड अभी क्षमता उपयोग के उच्च स्तर पर चल रहा है, और डबलिंग से भीड़ कम होगी, समय की पाबंदी बढ़ेगी और पूरे गलियारे की दक्षता मजबूत होगी। यह परियोजना कोचीन बंदरगाह से जुड़ी माल दुलाई कनेक्टिविटी को भी समर्थन देगी। इससे लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन आसान होंगे और इलाके का आर्थिक विकास होगा।

कालीपहाड़ी बाईपास लाइन (4.75 km), पूर्वी रेलवे: ₹107.10 करोड़

भारतीय रेल ने आसनसोल इलाके में परिचालन समस्याओं को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल में पूर्वी रेलवे के तहत 107.10 करोड़ की लागत से 4.75 किमी लंबी कालीपहाड़ी बाईपास लाइन बनाने की भी मंजूरी दी है। अभी, दक्षिण पूर्वी रेलवे और पूर्वी रेलवे के बीच चलने वाली ट्रेनों को इंजन रिवर्सल के लिए आसनसोल यार्ड में जाना पड़ता है, जिससे जाम लगता है। ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनसे बचा जा सकता है और अवसंरचना का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। प्रस्तावित बाईपास लाइन दोनों जोन के बीच सीधी कनेक्टिविटी देगी, जिससे यार्ड में इंजन रिवर्सल की जरूरत खत्म हो जाएगी। इस परियोजना से हर दिन लगभग नौ मालगाड़ियों के लिए लगभग 90 मिनट और आठ कोचिंग ट्रेनों के लिए लगभग 30 मिनट का समय बचने की उम्मीद है। यार्ड में जाम कम करके और परिचालन आसानी में सुधार करके, यह बाईपास लाइन की क्षमता बढ़ाएगी, टर्नअराउंड टाइम कम करेगी और पूर्वी भारत के सबसे व्यस्त रेलवे क्षेत्रों में से एक में दक्षता में काफी सुधार करेगी।

इन परियोजनाओं की मंजूरी के साथ, भारतीय रेल आधुनिक, कुशल और उच्च क्षमता वाले रेल नेटवर्क के अपने विजन को आगे बढ़ा रही है। रखरखाव सेवा को आधुनिक बनाने, कॉरिडोर डबलिंग और परिचालन में भीड़ कम करने लक्ष्य पर आधारित निवेश के जरिए, नेशनल परिवहन सेवा यात्रियों और उद्योग दोनों के लिए तेज, सुरक्षित और ज्यादा भरोसेमंद सेवा देने की प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है। इसके साथ ही रेलवे भारत की आर्थिक वृद्धि की रीढ़ को भी मजबूत कर रही है।



मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा चार लेन दोराहा रेलवे ओवर ब्रिज: श्री रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय राज्य मंत्री (रेलवे एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग)

सूत्र/रे.स.ब्यू- लेवल क्रॉसिंग संख्या 164एबी, दोराहा पर चार लेन रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण मालवा क्षेत्र, पंजाब की राजधानी तथा आसपास के जिलों के बीच संपर्क को मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजना साबित होगा। यह बात केंद्रीय राज्य मंत्री (रेलवे एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कही। कार्यक्रम में श्री विनोद भाटिया, मंडल रेल प्रबंधक, अंबाला, श्री राजीव रंजन राजू, चीफ इंजीनियर (रोड सेपटी प्रोजेक्ट) एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मीडिया से बातचीत करते हुए, चार लेन आरओबी का शिलान्यास करने के बाद मंत्री ने बताया कि लगभग ₹70-55 करोड़ की लागत से बनने वाली यह परियोजना अगले एक वर्ष के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अब इस कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पिछले लगभग 12 वर्षों से इस लेवल क्रॉसिंग पर लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, जिससे अब उन्हें राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि दोराहा का यह लेवल क्रॉसिंग रुपनगर से लुधियाना को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर स्थित है, जो पंजाब की राजधानी और पूरे मालवा क्षेत्र के बीच एक अहम कड़ी का काम करती है। मंत्री ने कहा कि प्रतिदिन लगभग 190 ट्रेनें इस क्रॉसिंग से गुजरती हैं और 3,000 से अधिक वाहन यहां से होकर निकलते हैं। रेल यातायात के कारण बार-बार फाटक बंद होने से जाम, लंबा इंतजार और आम यात्रियों, व्यापारियों तथा परिवहनकर्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरओबी के निर्माण से ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।

श्री रवनीत सिंह ने इस परियोजना को स्वीकृति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ी सौगात है। नया चार लेन आरओबी न केवल दैनिक आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि माल एवं सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित कर आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा।

पंजाब में चल रहे रेलवे बुनियादी ढांचा विकास कार्यों की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि राज्य में 166 स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज (ROB), रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) और लो हाइट सबवे (LHS) के कार्य 1,480.09 करोड़ की लागत से प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में रेलवे अवसंरचना विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है और सरकार राज्य में रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब में रेलवे का वार्षिक बजट आवंटन



2009-2014 की अवधि की तुलना में आज लगभग 25 गुना बढ़कर ₹5,673 करोड़ हो गया है। वर्तमान में राज्य में 26,382 करोड़ के अवसंरचना कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें नई रेल लाइनों का निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास, सुरक्षा उन्नयन तथा क्षमता विस्तार से जुड़े कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 30 रेलवे स्टेशनों का ₹1,311 करोड़ की लागत से व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

मंत्री ने दिल्ली और अंबाला के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। यह परियोजना अत्यधिक व्यस्त दिल्ली जम्मू रेल कॉरिडोर को चौड़ा करने की व्यापक योजना का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को उत्तरी राज्यों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

दिल्ली - अम्बाला खंड देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है, जहां यात्री और माल यातायात दोनों का भारी दबाव है। तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण से लाइन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, परिचालन दक्षता सुधरेगी और भीड़भाड़ में कमी आएगी। 194 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹5,983 करोड़ है और इसे चार वर्षों में पूरा किया जाएगा। यह परियोजना हरियाणा के सोनीपत, पानीपत,

करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिलों तथा दिल्ली के सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।

क्षमता वृद्धि से अतिरिक्त यात्री एवं मालगाड़ियों का संचालन संभव होगा, जिससे समयपालन और सेवा की विश्वसनीयता में सुधार आएगा। यह कॉरिडोर रोपड़, पानीपत और राजपुरा स्थित ताप विद्युत संयंत्रों सहित कृषि गोदामों और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ता है। बेहतर माल परिवहन से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

उन्नत कॉरिडोर से प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों जैसे श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, श्रीनगर, जम्मू, शिमला तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जिससे पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, यह परियोजना प्रतिवर्ष लगभग 24.6 मिलियन टन अतिरिक्त माल परिवहन को संभव बनाएगी, जिससे मौजूदा ढांचे पर दबाव कम होगा। पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रतिवर्ष लगभग 43 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 1.7 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। अनुमानित रूप से 952 करोड़ प्रति वर्ष की लॉजिस्टिक लागत बचत होगी, जिससे आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। निर्माण चरण के दौरान लगभग 132 लाख मानव-दिवस के रोजगार सृजित होने की संभावना है।

रेलवे पेंशनभोगियों के लिए चेतावनी

साइबर जालसाज सक्रिय, गोपनीय जानकारी साझा न करें



सूत्र/रे.स.ब्यू- रेलवे पेंशनभोगियों को साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुछ साइबर जालसाज रेलवे अधिकारियों के नाम पर फर्जी फोन कॉल कर रहे हैं तथा एसएमएस और व्हाट्सएप संदेश भेजकर पेंशनभोगियों से व्यक्तिगत एवं वित्तीय विवरण मांग रहे हैं। इन संदेशों और कॉल में पीपीओ अपडेट, केवाईसी सत्यापन, अतिरिक्त पेंशन लाभ आदि का बहाना बनाकर बैंक खाते की जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड तथा अन्य गोपनीय सूचनाएं मांगी जा रही हैं। भारतीय रेलवे द्वारा स्पष्ट किया गया है कि

रेलवे पीपीओ या सेवा रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कोई लिंक या संदेश जारी नहीं करता। किसी भी रेलवे अधिकारी को फोन कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से बैंक विवरण, ओटीपी, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है। पेंशनभोगियों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और अपने परिवार के सदस्यों को भी इस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करें। किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश की सूचना तुरंत पुलिस साइबर सेल और संबंधित प्रशासनिक कार्यालय को दें।

त्वरित कार्रवाई का उदाहरण: रेलवे कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता

सूत्र/रे.स.ब्यू- श्री राकेश कुमार, एक्स-ट्रैक मटेनर-II, जो सहायक मंडल अभियंता/रोहताक के अधीन कार्यरत थे, दिनांक 13/12/2025 की ऑफ ड्यूटी में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके परिवार में उनकी विधवा (श्रीमती मोनिका) और तीन छोटी बेटियाँ हैं। उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट था और वे रेलवे सैलरी पैकेज स्कीम के तहत लाभार्थी थे। उनकी मौत की खबर के तुरंत बाद, उनके 1 करोड़ रुपये के एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस क्लेम के भुगतान का केस शुरू किया गया।

उनकी विधवा, श्रीमती मोनिका को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केस को चलाया गया। उन्हें नियुक्ति देकर पद दिया गया है। उन्हें, श्री पुष्पेश रमण त्रिपाठी

मंडल रेल प्रबंधक, दिल्ली ने नियुक्ति पत्र दिया। इसके अलावा, विधवा, श्रीमती मोनिका को सभी सेटलमेंट भुगतान कर दिए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिकारियों और इंश्योरेंस कंपनी की कोशिश से, 1 करोड़ रुपये का क्लेम अमाउंट बेनिफिशियरी श्रीमती मोनिका के बैंक अकाउंट में भेज दिया गया। 1 करोड़ रुपये का सेरेमोनियल चेक श्रीमती मोनिका को श्री पुष्पेश रमण त्रिपाठी मंडल रेल प्रबंधक, दिल्ली ने दिया। सुश्री सुचित्रा जैन एवं सुश्री ज्योत्सना रानी मोहराना दोनों डी.जी.एम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली मंडल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अन्य अधिकारी एवं रेलवे यूनियन तथा एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद थे।

महाप्रबंधक/उत्तर मध्य रेलवे ने अलीगढ़-चिपियाना बुजुर्ग खंड का किया विंडो-ट्रेलिंग निरीक्षण

दादरी से ट्रेनों के संभावित संचालन के दृष्टिगत विभिन्न स्टेशनों का लिया जायजा

सूत्र/उत्तर मध्य रेलवे- दिनांक 25 फरवरी 2026 को महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे श्री नरेश पाल सिंह द्वारा अलीगढ़ चिपियाना बुजुर्ग रेल खंड का निरीक्षण यान से विंडो-ट्रेलिंग निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे श्री एस. एस. चंद्रायन, प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री ए. के. द्विवेदी, अपर मंडल रेल प्रबंधक/इंफ्रा श्री नवीन प्रकाश, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री अकांश गोविल, वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर श्री अविलय यादव, उप मुख्य यातायात प्रबंधक टूंडला श्री अमित आनंद सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विंडो-ट्रेलिंग निरीक्षण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण निरीक्षण पद्धति है, जिसके अंतर्गत चलती ट्रेन/निरीक्षण यान से रेलपथ एवं उससे संबंधित अवसंरचनाओं का सूक्ष्म अवलोकन किया जाता है। निरीक्षण के दौरान सिग्नलिंग व्यवस्था, ओएचई (विद्युत लाइन), प्लेटफॉर्म, समपार फाटक, ट्रैक की स्थिति, ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स (TGI), प्वाइंट एवं क्रॉसिंग, सिग्नल दृश्यता, स्टेशन स्वच्छता तथा यात्री सुविधाओं सहित विभिन्न संरक्षा एवं परिचालन मानकों की विस्तृत समीक्षा की गई।

निरीक्षण के क्रम में महाप्रबंधक द्वारा गाजियाबाद स्थित मेमू शोड का भी निरीक्षण किया गया तथा वहां उपलब्ध अनुरक्षण सुविधाओं एवं कार्यप्रणाली का गहन अवलोकन किया गया। इसके अतिरिक्त दादरी स्थित नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेशन परिसर का भ्रमण कर रेलवे एवं विद्युत उत्पादन इकाई के मध्य समन्वय तथा कोयला आपूर्ति व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ते शहरी एवं औद्योगिक विस्तार तथा भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दादरी स्टेशन से ट्रेनों के संचालन की संभावनाओं का व्यावहारिक आकलन करना था। दादरी से ट्रेनों का संचालन प्रारंभ होने पर ग्रेटर नोएडा, दादरी एवं आसपास के औद्योगिक तथा आवासीय क्षेत्रों के



यात्रियों को निकटतम रेल सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे दूरवर्ती स्टेशनों पर निर्भरता कम होगी और प्रमुख स्टेशनों पर यात्री दबाव में कमी आएगी। साथ ही क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने तथा यातायात के संतुलित वितरण में भी सहायता मिलेगी। इसी उद्देश्य से दादरी, मारीपथ एवं चिपियाना बुजुर्ग स्टेशनों का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान किए गए। इसी क्रम में महाप्रबंधक महोदय ने हरदुआगंज का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हरदुआगंज यार्ड का विस्तृत जायजा लिया, निर्माणाधीन हरदुआगंज फ्लाईओवर की प्रगति की समीक्षा की तथा गुड्स शोड

परिसर में चल रहे कार्यों और अतिरिक्त लाइन के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से प्रगति एवं समयबद्ध पूर्णता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। महाप्रबंधक महोदय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्ता एवं संरक्षा मानकों के अनुरूप पूर्ण कराए जाएं तथा परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं अग्रिम रूप से सुनिश्चित की जाएं।



संरक्षा और सुरक्षा जागरूकता वीडियो किए जा रही संरक्षा समीक्षा बैठक में

स्वामियों के प्रति “जीरो टॉलरेंस” का आह्वान

उत्तर मध्य रेलवे जोन में संरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाप्रबंधक श्री नरेश पाल सिंह ने उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय संरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान दो विशेष संरक्षा जागरूकता वीडियो जारी किए। प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी श्री जे.सी.एस. बोरा और सभी विभाग के प्रधान विभागाध्यक्ष और मंडल रेल प्रबंधकों सहित वरिष्ठ मंडल अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संभावित जोखिम कारकों की पहचान करना और परिचालन संरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय लागू करना था। जारी किए गए दोनों वीडियो महत्वपूर्ण ‘विजुअल सोशल अवेयरनेस’ टूल के रूप में कार्य करेंगे, जिन्हें आम जनता और यात्रियों द्वारा पालन किए जाने वाले विभिन्न संरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रथम वीडियो में स्वयं ट्रेन द्वारा एक संरक्षा संदेश दिया गया है, जो पथराव (Stone Pelting), अनधिकृत स्थानों से रेल पटरी पार करने, बंद लेवल क्रॉसिंग गेटों को पार करने और मवेशियों के ट्रेन से टकराने जैसी सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करता है। दूसरा वीडियो मुख्य रूप से ‘मैन रन ओवर’ (Man Run Over) की समस्या पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते समय रेलवे ट्रैक पार न करने के प्रति सचेत करना है।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने महाराष्ट्र के बुलढाणा स्थित शेगांव में ‘राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026’ का उद्घाटन किया

राष्ट्रीय आरोग्य मेला भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का ‘महाकुंभ’ है: आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव

सूत्र/रे.स.ब्यू- राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में ‘राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026’ का उद्घाटन किया। आयुष मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस के सहयोग से आयोजित यह चार दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, किसानों, उद्योग प्रतिनिधियों और नागरिकों को एक साझा मंच पर लाया है।

श्रीमती मुर्मु ने कहा कि संत श्री गजानन महाराज की पावन धरा पर उपस्थित होकर उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में आने से पहले उन्हें उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। उन्होंने याद किया कि संत गजानन महाराज ने अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और सभी जीवों के लिए करुणा और समानता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को समर्पित कार्यक्रम का उद्घाटन करना बड़े संतोष का विषय है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी परंपरा में कहा गया है, ‘‘आरोग्यम परमम सुखम्’’, जिसका अर्थ है कि अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक स्वस्थ शरीर सभी कर्तव्यों के पालन के लिए प्राथमिक साधन है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को मजबूत करने में स्वस्थ नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रेखांकित किया कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी ने निवारक, संवर्धक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल में अमूल्य योगदान दिया है और समाज का संतुलित जीवन की ओर मार्गदर्शन करना जारी रखा है।

श्रीमती मुर्मु ने कहा कि दुनिया तेजी से इस बात को स्वीकार कर रही है कि वास्तविक कल्याण के लिए शरीर और मन के बीच सामंजस्य आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आयुष प्रणालियां केवल उपचार ही नहीं, बल्कि संतुलित आहार, दैनिक और मौसमी दिनचर्या, योग, ध्यान और प्राकृतिक उपचारों पर आधारित एक व्यापक जीवनशैली ढांचा प्रदान करती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीमारियों का बोझ कम करने और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए निवारक और समग्र स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक है।

राष्ट्रपति ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत औषधीय पौधों और पारंपरिक ज्ञान की समृद्ध विरासत का धनी है। औषधीय पौधों के संरक्षण और वैज्ञानिक खेती के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कच्चे माल के आधार को मजबूत करने से सतत स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। उन्होंने आयुष प्रणालियों को आगे बढ़ाने और एक स्वस्थ एवं सशक्त भारत के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया।

महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने आयुर्वेद को भारत के प्राचीन ऋषियों द्वारा स्थापित एक शाश्वत वैज्ञानिक परंपरा बताया, जिन्हें उन्होंने भारत के सबसे पुराने रिसर्च स्कॉलर बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पांच तत्वों से निर्मित मानव शरीर को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही सर्वोत्तम रूप से स्वस्थ रखा जा सकता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल से बेहतर है।

राज्यपाल ने कहा कि भारत की पारंपरिक प्रणालियां गहन वैज्ञानिक हैं और सदियों के अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित हैं। उन्होंने चिकित्सकों से

प्रामाणिकता बनाए रखने, दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अपने-अपने विषयों में अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को मजबूत करने के लिए आयुष मंत्रालय को बधाई दी।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने राष्ट्रीय आरोग्य मेले को ‘‘भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का महाकुंभ’’ बताया। उन्होंने कहा कि यह भव्य समागम नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, उद्योग प्रतिनिधियों, किसानों और चिकित्सकों को एक साझा मंच पर लेकर आया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मेला केवल एक स्वास्थ्य शिविर नहीं है, बल्कि भारत की समग्र स्वास्थ्य देखभाल परंपराओं को मजबूत करने और उन्हें सीधे जनता से जोड़ने की एक सशक्त राष्ट्रीय पहल है।

श्री जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रालय साक्ष्य-आधारित आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और अन्य आयुष विषयों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक विश्वसनीयता दिलाने के लिए केंद्रित अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रमाणीकरण, गुणवत्ता आश्वासन और मानकीकरण को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक



वै

ज्ञानिक मानकों के साथ जोड़ने से आयुष में वैश्विक विश्वास और बढ़ेगा।

आयुष पर्यटन की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए श्री जाधव ने कहा कि भारत समग्र कल्याण के क्षेत्र में ‘‘वैश्विक अग्रणी देश’’ बन सकता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्साओं के माध्यम से भारत वैश्विक कल्याण आंदोलन का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। उन्होंने आगे कहा कि आयुष पर्यटन के विस्तार से न केवल भारत एक वैश्विक कल्याण गंतव्य के रूप में स्थापित होगा, बल्कि इससे रोजगार भी पैदा होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और औषधीय पौधों की खेती में लगे किसानों को लाभ होगा।

महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री मकरंद जाधव पाटिल ने कहा कि शेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेले की मेजबानी करना महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मेले में निःशुल्क परामर्श, दवा वितरण, विशेषज्ञों के व्याख्यान और औषधीय पौधों की खेती में लगे किसानों के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि आरोग्य मेले जनभागीदारी, जागरूकता पैदा करने और प्रामाणिक आयुष प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने गुणवत्ता, अनुसंधान प्रगति और वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करने के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता दोहराई।

राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 में केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री रक्षा खडसे, श्री संजय कुटे, वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, आयुष विशेषज्ञों, किसानों, चिकित्सकों और सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इन सभी लोगों ने भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों, कल्याण पर्यटन और समग्र स्वास्थ्य देखभाल पहलों को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आयुर्वेद में असाधारण योगदान देने के सम्मान में प्रतिष्ठित चिकित्सकों को ‘आजीवन आयुर्वेदिक गौरव सम्मान’ प्रदान किया। पुरस्कार विजेताओं में वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा, वैद्य राकेश शर्मा, डॉ. आशुतोष गुप्ता, डॉ. मनीषा कोटेकर, पीएम वेरियर और डॉ. रामदास शामिल थे, जिनकी समर्पित सेवा और नवोन्मेषी कार्यों ने आयुष प्रणालियों के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा, जन स्वास्थ्य पहलों और सामुदायिक कल्याण को काफी आगे बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का दौरा भी किया।

इंडिया-एआई इपैक्ट समिट में आयुष: दर्शकों की व्यापक भागीदारी ने नागरिक केंद्रित डिजिटल आयुष समाधानों में बढ़ती दिलचस्पी को रेखांकित किया

आयुष डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत के स्वदेशी आयुष मॉडलों का लाभ उठाया जाए: सचिव, आयुष मंत्रालय

सूत्र/रे.स.ब्यू-इंडिया-एआई इपैक्ट समिट 2026 में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के पैवेलियन में दर्शकों, नवोन्मेषकों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों का तांता लगा रहा। इन सब ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए मंत्रालय कृत्रिम मेधा (एआई) समर्थित समाधानों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पैवेलियन में एआई चालित चैटबॉट्स और योगा पॉस्चर एआई ने खास तौर से काफी दिलचस्पी पैदा की। कंप्यूटर दृष्टि आधारित समाधान योगा पॉस्चर एआई उपयोगकर्ताओं को योग आसनों के आकलन, सुधार तथा अधिक सटीक और सुरक्षित ढंग से अभ्यास में समर्थ बनाता है। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के महानिदेशक वैद्य रविनारायण आचार्य और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित वस्तुओं का अवलोकन किया जो डिजिटल पहलकदमियों और प्रौद्योगिकी समर्थित जन स्वास्थ्य टूल्स की झांकी पेश करते हैं। श्री कोटेचा ने आयुष क्षेत्र में सेवा डिलीवरी, अनुसंधान, शिक्षण और प्रशासन को मजबूत करने के लिए तैयार किए गए प्रौद्योगिकी संचालित हस्तक्षेपों के सुव्यवस्थित और प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए आयुष ग्रिड टीम की सराहना की। आयुष सचिव ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सर्वम एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मेटा और गूगल समेत अन्य प्रमुख संस्थाओं की प्रदर्शिनियों का अवलोकन किया और सारगर्भित संवाद किए। श्री कोटेचा ने नागरिकों, चिकित्सकों और संस्थानों की सहायता के लिए विकसित एआई आधारित चैटबॉट्स की व्यावहारिक उपयोगिता का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पारंपरिक स्वास्थ्यसेवा की संरचना में डिजिटल बुद्धिमत्ता को शामिल करने के मौजूदा प्रयासों को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्होंने स्वास्थ्यसेवा के कायाकल्प के लिए स्वदेशी एआई क्षमताओं के रणनीतिक महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि डाटा की प्रामाणिकता, समावेशिता और वैश्विक अंतरसंचालनीयता को सुनिश्चित करते हुए आयुष डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत के स्वदेशी एआई मॉडलों का लाभ उठाया जाना चाहिए। आयुष सचिव ने कहा कि मापनीय और जनकेंद्रित स्वास्थ्य सेवा समाधानों की रचना के लिए पारंपरिक ज्ञान के साथ कृत्रिम मेधा को जिम्मेदारी पूर्वक जोड़ा जाना चाहिए।

शिखर सम्मेलन में आयुष पवेलियन ‘आयुष ग्रिड’ की व्यापक संरचना को प्रस्तुत करता है, जो पारंपरिक चिकित्सा के लिए भारत की डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसररचना है। इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख घटक ‘माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल (एमएआईएसपी)’ है। यह एक एकीकृत डिजिटल गेटवे है जो स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, अनुसंधान, औषधीय पौधों की जानकारी, औषधि प्रशासन और सार्वजनिक पहुंच को एक ही मंच के माध्यम से जोड़ता है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों और संस्थानों के लिए प्रामाणिक आयुष सेवाओं तक निर्बाध और तकनीक-समर्थित पहुंच सुनिश्चित करना है।



एआई-सक्षम उपकरणों का सजीव प्रदर्शन दर्शकों के लिए संवाद का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इंटेलिजेंट चैटबॉट्स व्यक्तिगत कल्याण मार्गदर्शन और सेवाओं तक पहुंचने में सहायता प्रदान करते हैं, जबकि ‘योग पोस्चर एआई’ प्रणाली यह प्रदर्शित करती है कि कैसे वास्तविक समय में मुद्रा विश्लेषण योग के अभ्यास में सटीकता, सुरक्षा और सुलभता को बढ़ा सकता है। यह पवेलियन आयुष के विभिन्न विषयों में नैदानिक निर्णय लेने, मानकीकरण, अनुसंधान विश्लेषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुंच में सहायता करने के लिए विकसित किए जा रहे एआई उपकरणों को भी प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, सम्मेलन में आईआईटी जोधपुर उत्कृष्टता केंद्र की पहलकदमियों को भी प्रस्तुत किया गया, जिनमें डिजिटल स्वास्थ्य, कृत्रिम मेधा और पारंपरिक चिकित्सा के एक साथ प्रयोग पर शोध को उजागर किया गया है। इंटरैक्टिव डिस्प्ले (संवादात्मक प्रदर्शन) के माध्यम से सहयोगी अनुसंधान और पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में उभरते एआई अनुप्रयोगों की जानकारी दी गई।

‘इंडियाएआई आयुष मंत्रालय नवाचार चुनौती’ ने भी पवेलियन का दौरा करने वाले स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के बीच काफी रुचि जगाई, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुप्रयोगों के लिए एआई-संचालित समाधानों के प्रति बढ़ती सक्रियता को दर्शाता है।

इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में आयुष मंत्रालय की भागीदारी से यह प्रदर्शित किया गया कि कैसे उन्नत प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार उपयोग से पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान प्रणालियों को सशक्त बनाया जा सकता है। यह प्रयास एआई के समावेशी और जन-केंद्रित अनुप्रयोगों पर व्यापक वैश्विक चर्चा में अपना

अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2026 में वैश्विक स्वास्थ्य विमर्श के केंद्र में उभरा आयुष

सूत्र/रे.स.ब्यू- आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव ने दुबई में आयोजित तृतीय अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (IACE 2026) का उद्घाटन किया और बाद में उसके समापन सत्र को संबोधित किया, जो पारंपरिक और समेकित स्वास्थ्य प्रणालियों की वैश्विक स्वीकृति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ।

मंत्री ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित कीं और एक एकीकृत, निवारक तथा सतत वैश्विक स्वास्थ्य पारितंत्र के निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

विश्व भर से आए अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों, शोधकर्ताओं, उद्योग नेताओं और प्रैक्टिशनरों को संबोधित करते हुए श्री जाधव ने कहा कि आयुष प्रणालियाँ आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी प्रकृति के साथ सामंजस्य में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को संबोधित करने वाले समग्र दृष्टिकोण के रूप में बढ़ती हुई मान्यता प्राप्त कर रही हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वभर में बढ़ती जीवनशैली संबंधी बीमारियाँ, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ निवारक और समग्र समाधानों की मांग करती हैं, और आयुष शरीर, मन और पर्यावरण को एकीकृत करने वाले प्रमाण-समर्थित हस्तक्षेप प्रदान करता है।

तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान लगभग 28 देशों के प्रतिभागियों ने परामर्श, वैज्ञानिक चर्चाओं और साझेदारियों में भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पारंपरिक चिकित्सा अब वैश्विक स्वास्थ्य संवाद के केंद्र में है।

सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम मन-शरीर स्वास्थ्य के लिए आयुष हस्तक्षेपों पर एक प्रारूप अंतरराष्ट्रीय श्वेतपत्र (व्हाइट पेपर) पर विस्तृत विचार-विमर्श रहा। इस दस्तावेज का उद्देश्य वैश्विक समझ को अनुभव-आधारित प्रथाओं से प्रमाण-आधारित सत्यापन की ओर, अलग-थलग पद्धतियों से संरचित उपचार प्रोटोकॉल की ओर, और समानांतर प्रणालियों से एकीकृत स्वास्थ्य ढाँचों की ओर ले जाना है। अंतिम रूप दिए जाने के बाद, इसके सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और समेकित चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में कार्यरत अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करने की अपेक्षा है।

मंत्री ने याद दिलाया कि पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन, जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, तथा दिल्ली घोषणा ने पारंपरिक चिकित्सा के प्रमाण सृजन, सुरक्षा मानकों और जिम्मेदार एकीकरण की दिशा में वैश्विक प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की थी। उन्होंने रेखांकित किया कि इस सम्मेलन ने संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों, शैक्षणिक आदान-प्रदान, नियामकीय सहयोग, निवेश साझेदारियों तथा मेडिकल वैल्यू ट्रेवल और आयुष सेवाओं के विस्तार को बढ़ावा देकर इस वैश्विक गति को आगे बढ़ाया। उन्होंने आयुष उत्पादों और सेवाओं की वैश्विक स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन, फार्माकोपियल अनुपालन और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

श्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच वैज्ञानिक संवाद, स्वास्थ्य कूटनीति और देशों के बीच विश्वास को मजबूत करते हैं, और इस बात पर बल दिया कि आयुष संस्कृतियों और स्वास्थ्य प्रणालियों को जोड़ने वाले सेतु के रूप में कार्य कर सकता है, साथ ही वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और निवारक देखभाल का समर्थन कर सकता है। भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि भारत एक एकीकृत, प्रमाण-आधारित और मानव-केंद्रित वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना के निर्माण के लिए साझेदार देशों के साथ नेतृत्व करने और सहयोग देने के लिए तैयार है।

सम्मेलन को सफल घोषित करते हुए श्री जाधव ने कहा कि विचार-विमर्श को कार्यान्वित परिणामों और संस्थागत साझेदारियों में परिवर्तित होना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये चर्चाएँ वैज्ञानिक सहभागिता, साझेदारियों और वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक विश्वसनीय योगदानकर्ता के रूप में आयुष की स्थिति को और सुदृढ़ करेंगी।

महाप्रबंधक/एमसीएफ द्वारा वंदे भारत प्रोटोटाइप रेल का निरीक्षण, प्रारंभिक ट्रायल सफलतापूर्वक सम्पन्न



सूत्र/रे.स.ब्यू- श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा, महाप्रबंधक, एमसीएफ ने दिनांक 20.02.2026 को कारखाना परिसर में वंदे भारत प्रोटोटाइप रेल का निरीक्षण किया। यह वंदे भारत परियोजना की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निरीक्षण के दौरान कारखाना परिसर में प्रथम चरण के गति परीक्षण सम्पन्न किए गए। इस अवसर पर एमसीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, मेसर्स सीमेन्स के प्रतिनिधि तथा अन्य उद्योग सहयोगी उपस्थित रहे। ड्राइवर केबिन से प्रमुख ऑनबोर्ड प्रणालियों का परीक्षण किया गया। सीमेंस की टीम द्वारा पैंटोग्राफ वीसीबी (वैक्यूम सर्किट ब्रेकर) संचालन तथा उच्च वोल्टेज आदि का निरीक्षण किया गया। ये सभी क्रियाएं ड्राइवर डेस्क यूनिट (DDU) से सफलतापूर्वक संचालित की गई, जिससे प्रणाली की समन्वित कार्यक्षमता एवं परिचालन तत्परता प्रदर्शित हुई। एक लघु ट्रायल रन भी किया गया, जिसमें ट्रेक्शन, गति तथा ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) से लिए गए करंट जैसे प्रमुख परीक्षण मानकों का अवलोकन किया गया। ट्रायल शेड से प्रारंभिक संचालन के दौरान रेल की गति को 10 किमी/घंटा की सीमित निर्धारित गति पर परीक्षण किया गया। ब्रेक प्रतिक्रिया, पैसेंजर एनाउंसमेंट एवं पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (PAPIS) की कार्यप्रणाली तथा ट्रेक्शन के दौरान प्रणाली के व्यवहार का भी परीक्षण किया गया।

रेल का विस्तृत निरीक्षण भी किया गया, जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का सत्यापन शामिल था। महाप्रबंधक महोदय ने प्रकाश व्यवस्था के समुचित एलाइनमेंट तथा विद्युत क्यूबिकल्स की वैक्यूम एवं मैग्नेटिक क्लीनिंग के माध्यम से गहन सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी धात्विक अवशेष को हटाकर उच्चतम सुरक्षा एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। यह उपलब्धि एमसीएफ एवं उसके उद्योग सहयोगियों के बीच सुदृढ़ समन्वय एवं सहयोग का प्रतीक है, जो वंदे भारत परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

महाप्रबंधक श्री आशुतोष पंत ने बरेका न्यू ब्लॉक शॉप का किया गहन निरीक्षण

सूत्र/रे.स.ब्यू- दिनांक 26 फरवरी, 2026 को बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) के महाप्रबंधक श्री आशुतोष पंत ने परियोजनाओं के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से बरेका कर्मशाला स्थित न्यू ब्लॉक शॉप एवं मॉडर्न सांठ का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों का विस्तार से अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं तकनीकी मानकों के पालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।



महाप्रबंधक श्री पंत ने निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने, सुरक्षा मानकों के पूर्ण अनुपालन तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूर्ण करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं सर्वोत्तम इंजीनियरिंग तकनीकों के साथ संपन्न किए जाएं, जिससे उत्पादन क्षमता एवं कार्यकुशलता में और अधिक वृद्धि सुनिश्चित हो सके। निरीक्षण के दौरान प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री विवेक शील, प्रमुख मुख्य इंजीनियर



श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विद्युत सर्विस इंजीनियर श्री मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर (विद्युत) श्री अनुराग कुमार गुप्ता, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर (ई. एल. परियोजना) श्री कौशलेश सिंह, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (डीजल, पीओएच) श्री एस.बी. पटेल, उप मुख्य इंजीनियर श्री साकेत एवं उप महाप्रबंधक श्री सागर उपस्थित रहे। महाप्रबंधक द्वारा किया गया यह निरीक्षण बरेका में चल रही अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण पहलों की प्रगति की समीक्षा तथा भावी उत्पादन आवश्यकताओं की तैयारी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।

वित्त वर्ष 2025-26 में मध्य रेल ने 1373 मिलियन से अधिक यात्रियों को परिवहन प्रदान किया

मुंबई उपनगरीय ट्रेन सेवाओं ने जनवरी 2026 में 127 मिलियन से अधिक यात्रियों को परिवहन प्रदान किया

सूत्र/रे.स.ब्यू- वित्त वर्ष 2025-26 (जनवरी 2026 तक) के दौरान मध्य रेल ने यात्री परिवहन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, जिसमें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों खंडों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। मध्य रेल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 1373.39 मिलियन यात्रियों को परिवहन प्रदान किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में परिवहन किए गए 1348.33 मिलियन यात्रियों की तुलना में 1.86% की वृद्धि दर्शाता है। जनवरी 2026 के दौरान, मध्य रेल ने 146.29 मिलियन यात्रियों (जिनमें 129.08 मिलियन उपनगरीय और 17.2 करोड़ गैर-उपनगरीय यात्री शामिल हैं) का परिवहन किया। 129.08 मिलियन उपनगरीय यात्रियों में मुंबई उपनगरीय लाइन पर 127.12 मिलियन और पुणे उपनगरीय लाइन पर 1.96 मिलियन यात्री शामिल हैं। नेरूल/बेलापुर-उरण खंड पर अतिरिक्त सेवाओं की शुरुआत और इस मार्ग पर दो नए स्टेशनों, तरघर और गवान स्टेशनों के चालू होने से उपनगरीय ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। हार्बर लाइन पर एसी सेवाओं की शुरुआत को जबरदस्त प्रतिसाद मिला है, जिसके चलते महज 16 दिनों में 6 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की है। यह यात्रियों की बेहतर सुविधा और दक्षता के प्रति प्रबल रुचि को दर्शाता है।

- वित्त वर्ष 2025-26 में उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1201.93 मिलियन है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1187.92 मिलियन थी।
- वित्त वर्ष 2025-26 में मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर और अन्य गैर-उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 171.46 मिलियन थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 160.41 मिलियन थी।

सुरक्षा और तकनीक का संगम: रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने DFCCIL संचालन के लिए साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने पर दिया जोर

सूत्र/रे.स.ब्यू- रेलवे सुरक्षा में तकनीक आधारित सुधारों को गति देते हुए, रेलवे सुरक्षा आयुक्त (पूर्वोत्तर परिमंडल) श्री प्रणजीव सक्सेना ने DFCCIL के अ परेशन कंट्रोल सेंटर (OCC) का दौरा किया। बढ़ते डिजिटल खतरों के बीच उन्होंने मजबूत साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स और सर्वर रिकॉर्ड संरक्षण की वकालत की। उप मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त (तकनीकी) श्री आशीष पांडेय और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ, श्री सक्सेना ने डिजिटल हो रहे रेल संचालन को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया। गहन चर्चा के दौरान उन्होंने जोर देकर कहा की हमारे सिस्टम की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल एक परिचालन आवश्यकता नहीं है बल्कि यह उन लोगों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है जो प्रतिदिन हमारी सेवाओं पर भरोसा करते हैं। आयुक्त ने यातायात विभाग के सभी बोर्ड नियंत्रकों, ट्रेक्शन पावर कंट्रोलर, ट्रेक्शन एवं रोलिंग स्टॉक कंट्रोलर, एसएंडटी (S&T) कंट्रोलर, इंजीनियरिंग कंट्रोलर और सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने उनके कार्यों के परिणामों पर संतोष व्यक्त किया और उनके समर्पित प्रयासों की सराहना की।



इसके अतिरिक्त, उन्होंने SCADA, TMS, हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर, मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम और व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और परिणामों को अत्यधिक संतोषजनक पाया। बैठक के दौरान DFCCIL में ट्रेन संचालन और बुनियादी ढांचे के

विकास पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। चर्चा में संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि DFCCIL का रेल नेटवर्क तेजी से ऑनलाइन हो रहा है। डेटा एनालिटिक्स को एक अन्य प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया। अधिकारियों ने नोट किया कि यह ट्रेन शेड्यूलिंग, रखरखाव और सुरक्षा को बेहतर बनाने की शक्ति रखता है। डेटा एनालिटिक्स वे अंतर्दृष्टि (insights) प्रदान करता है जो दक्षता बढ़ाने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले सटीक निर्णय लेने के लिए आवश्यक हैं। तकनीकी युग में जवाबदेही के लिए सर्वर रिकॉर्ड संरक्षण भी चर्चा के केंद्र में रहा। यह दौरा माल दुलाई गलियारों (freight corridors) को सुरक्षित करने के लिए तकनीक और सुरक्षा के मेल के प्रति DFCCIL के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।



विस्टाडोम से कश्मीर दर्शन: बनिहाल-कटड़ा रेल खंड पर विशेष ट्रेन का शानदार संचालन

सूत्र/रे.स.ब्यू-उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने बड़गाम-बनिहाल मार्ग पर चलने वाली विशेष ट्रेन (गाड़ी संख्या 04688/04687) का विस्तार श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा तक कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यात्रियों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए इस ट्रेन में विस्टाडोम कोच (Vistadome Coach) जोड़ा गया है, जिसने अपनी पहली विस्तारित यात्रा में यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहले दिन विशेष ट्रेन का संचालन सफल रहा, जिसमें लगभग 600 से भी अधिक लोगों ने अपनी यात्रा का लुप्त उठाया। यात्रियों के हित में उठाए गए, इस ऐतिहासिक कदम पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने रेलवे के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि विशेष ट्रेन को बनिहाल से कटरा तक पहुंचाकर स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का विशेष लाभ दिया है।



यात्रियों ने अपनी यात्रा के दौरान विस्टाडोम कोच में कांच की छत और बड़ी पारदर्शी खिड़कियों से पहाड़ों, नदियों और सुरंगों के अद्भुत नजारों का आनंद लिया, साथ ही चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल और पहले केबल-स्टेजड अंजी पुल जैसे

इंजीनियरिंग अजूबों का दीदार किया।

ट्रेन के सफल संचालन पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, श्री उचित सिंघल ने कहा, कि यह एक पहल है, विस्टाडोम कोच के माध्यम से यात्रियों की यात्रा को प्राकृतिक नजारों के साथ सुगम बनाया जा सके, और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। आज पहले दिन इस विशेष ट्रेन के संचालन पर यात्रियों ने इसकी खुब सराहना करते हुए, अपनी यात्रा को और अधिक रोमांचक बनाया।



संपादकीय

भारतीय रेल की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार-‘नारी शक्ति’

जैसे-जैसे भारतीय रेलवे आधुनिकता और तकनीक के नए क्षितिज छू रही है, इस गौरवशाली यात्रा में हमारी महिला अधिकारियों और महिला कर्मचारियों की भूमिका पहले से कहीं अधिक प्रखर और महत्वपूर्ण होकर उभरी है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन अवसर पर, ‘रेल समाचार ब्यूरो’ भारतीय रेल के हर विभाग में कार्यरत उन हजारों महिलाओं को सलाम करता है, जो अपनी निष्ठा, साहस और बुद्धिमत्ता से राष्ट्र की जीवनरेखा को गतिमान रखे हुए हैं। भारतीय रेल में अब वह दौर बीत चुका है जब महिलाओं की भूमिका केवल कार्यालयों तक सीमित थी। आज रेल की पटरियों के रखरखाव से लेकर आसमान छूते सिग्नल टावरों तक, और भारी-भरकम लोकोमोटिव चलाने से लेकर स्टेशनों के कुशल प्रबंधन तक-हर जगह महिलाओं का ‘बोलबाला’ है। चाहे वह ट्रेन कंट्रोलर के रूप में जटिल ट्रैफिक को संभालना हो, ट्रैक मंटेनर के रूप में भीषण गर्मी और सर्दी में सुरक्षा सुनिश्चित करना हो, या उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में नीतिगत निर्णय लेना होय महिला रेलकर्मियों ने यह साबित कर दिया है कि उनमें चुनौतियों को अवसरों में बदलने की अद्भुत क्षमता है। हाल के वर्षों में भारतीय रेलवे में ‘महिला सशक्तिकरण’ के कई ऐतिहासिक उदाहरण देखे गए हैं। ‘ऑल-गुमेन’ ब्रू द्वारा संचालित ट्रेनें और पूरी तरह महिलाओं द्वारा प्रबंधित रेलवे स्टेशन इस बात का प्रमाण हैं कि जब अवसर मिलता है, तो भारतीय नारी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करती है। रेलवे जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में, जहाँ काम का दबाव और समय की पाबंदी अनिवार्य है, वहाँ ये महिलाएँ अपने घर और कर्तव्य के बीच जो संतुलन बनाती हैं, वह समाज के लिए प्रेरणादायक है। वे केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की वे गुमनाम नायक हैं जो हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने में सहायक बनती हैं। ‘रेल समाचार ब्यूरो’ के माध्यम से हम सभी महिला रेल अधिकारियों, लोको पायलटों, गार्डों, स्टेशन मास्टर्स, इंजीनियरों और सुरक्षा बल (RPF) की कर्मचारियों को बधाई देते हैं। आपकी अटूट कर्तव्यनिष्ठा ही है जो भारतीय रेल को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रखती है।

आप सभी को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की मंगलकामनाएँ!
- संपादक, रेल समाचार ब्यूरो

समस्त प्रकार के कानूनी मामलों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
दि. इलाहाबाद ब्लॉक वर्क्स प्रा. लि.
329/255 चक. जीरो रोड इलाहाबाद से मुद्रित
एवं 502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर,
कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।
आर.एन. आई नं. 51097-90 पोस्ट ए.डी.-8
मो. 9773946044 / 9793956044
फोन नं. 0532-2418040

पाठकों से अनुरोध

विगत वर्षों की भाँति आगामी वर्ष के लिए अपनी रेल समाचार ब्यूरो पत्रिका को सुरक्षित करने के लिए वार्षिक सन्तुष्टता शुल्क शीघ्र भेजने की कृपा करें, जिससे उक्त पत्रिका आपको नियमित भेजी जा सके।

सहयोग राशि:

१. उच्चतम अधिकारी-5000 रु. मात्र
२. उच्च अधिकारी-3500 रु. मात्र
३. अधीनस्थ अधिकारी-2500 रु. मात्र
४. रेलकमी/अन्य सदस्य-1000 रु. मात्र

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

पंजीकृत कार्यालय

502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड,
नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003
से प्रकाशित।

कॉप कार्यालय- अनिल केन (रिपोर्टर)
कार्यालय 8439 आर्य नगर
पहाड़गंज दिल्ली-55

Shri Rajesh Kumar Pandey Assumes Charge as General Manager of Northern Railway

Source/RSB- Shri Rajesh Kumar Pandey, a distinguished officer of the 1989 batch of the Indian Railway Service of Signal Engineering (IRSSE), has officially taken over as the General Manager of Northern Railway. A native of Gorakhpur, Uttar Pradesh, Shri Pandey brings a robust academic background to his new role. He earned his B.E. in Electronics from Madan Mohan Malaviya Engineering College, Gorakhpur, followed by an M.Tech from IIT Delhi. He began his illustrious career in the Indian Railways as an Assistant Signal and Telecom Engineer in Barauni. Since then, he has served in several high-impact roles across the railway network i.e Director of Inspection (in RDSO), where he overhauled quality assurance protocols, served as Additional Divisional Railway Manager (Samastipur) and Divisional Railway Manager (Pt. Deen Dayal Upadhyay Division). He held various senior capacities, notably spearheading the installation of axle counters in the Mumbai suburban section to ensure uninterrupted services during the monsoon.

Shri Pandey is widely recognized for his leadership in major infrastructure and safety projects. During his tenure as DRM, he played a critical role in the completion of the Eastern Dedicated Freight Corridor. He is also a key figure in the development and implementation of Kavach, India's indigenous Automatic Train Protection system. Most recently, as Additional Member (Signal) at the Railway Board, he successfully oversaw the installation of Kavach across a 400 km stretch, significantly enhancing rail safety.



Shri Mohit Chandra takes charges as General Manager, Chittaranjan Locomotive works

Source/RSB- Shri Mohit Chandra, a senior officer of the 1989 batch of the Indian Railway Service of Electrical Engineers, has officially taken over charge as the General Manager of Chittaranjan Locomotive Works (CLW) on 18 February 2026. Shri Chandra earned his Bachelor's degree in Electrical Engineering from the University of Roorkee and joined the Indian Railways. During his distinguished career, he has held a wide range of operational and maintenance responsibilities, including the upkeep of electric locomotive sheds, EMU car sheds, and electric locomotive operations at divisional, headquarters, and Railway Board levels.

He has also made notable contributions in the field of general administration, serving as Joint Secretary at the Union Public Service Commission, where he oversaw critical functions in the Services-I and Confidential wings.

Subsequently, he served as Divisional Railway Manager of the Prayagraj Division under the North Central Railway, further strengthening operational and administrative efficiency.

Before assuming charge as General Manager, CLW, Shri Chandra held the position of Additional General Manager of Northern Railway and earlier served as Principal Executive Director, Electrical Engineering (Rolling Stock), at the Railway Board, bringing with him extensive technical expertise and leadership experience.



Shri Manoranjan Pradhan Takes Charge as General Manager of Rail Wheel Factory



Source/RSB- Mechanical Engineering from University College of Engineering, Burla, he began his professional career with Tata Motors before joining Shri Manoranjan Pradhan, IRSS, has assumed charge as the General Manager of Rail Wheel Factory, Bengaluru, on 18 February 2026. Prior to this assignment, Shri Pradhan served as Principal Chief Materials Manager at Integral Coach Factory, Perambur, Chennai. A graduate in Indian Railways through the Indian Railway Stores Service cadre. Shri M. Pradhan brings with him rich and varied experience, having served in several key positions across major railway establishments. He has worked as Divisional Railway Manager, Kharagpur, apart from holding important assignments at Chittaranjan Locomotive Works, Eastern Railway, South Eastern Railway, South Western Railway and Southern Railway, in addition to his tenure at ICF. He took over the charge from Shri U. Subba Rao, GM/ICF, who held the concurrent charge of General Manager/RWF.

Shri Ajay Nandan assumes charges as General Manager, RCF Kapurthala



Source/RSB- Shri Ajay Nandan has assumed the charge of General Manager, Rail Coach Factory (RCF), Kapurthala on 17 February 2026. Shri Ajay Nandan is a 1989 batch officer of the Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME). Prior to his present appointment, he was serving as Principal Chief Mechanical Engineer (PCME) at North East Frontier Railway, Guwahati. With a distinguished career spanning over 35 years in Indian Railways, Shri Ajay Nandan has worked in various capacities across Zonal Railways, Production Units, Railway Divisions, and the Railway Board. Apart from his tenure as PCME at North East Frontier Railway, he has held several key assignments at New Delhi, Kolkata, Malda Town, Hajipur, Kota, Moradabad, Jamalpur and other important railway establishments. He also served as Divisional Rail Manager of Moradabad Division from 2021 to 2023. During his illustrious service, Shri Ajay Nandan has been the recipient of numerous awards and has also undergone advanced training programmes in India and abroad, enriching his technical and managerial expertise.

After assuming charge, General Manager Shri Ajay Nandan held an introductory meeting with all departmental heads in his office. During the meeting, a detailed presentation was made before the General Manager, highlighting an overall profile of Rail Coach Factory, Kapurthala, coach manufacturing activities, and various ongoing projects.

Shri Arvind Malkhede takes over as Principal Chief Operations Manager, Central Railway.

Source/RSB- Shri Arvind Malkhede has taken over as Principal Chief Operations Manager, Central Railway. He takes over from Shri S S Gupta who joined Railway Board as Principal Executive Director (Infrastructure). Shri Malkhede is a 1991 Batch IRTS Officer. He has worked in many important posts including Principal Chief Commercial Manager, Central Railway between 2024-2026, Senior Deputy General Manager, South Central Railway from the year 2022 to 2024 & Divisional Railway Manager (DRM), Hubballi Division, South Western Railway between the year 2019 to 2022.

He has also held a challenging post as Chief Freight Transportation Manager (CFTM) at North East Frontier Railway (NFR) during the year 2013-15 when gauge-conversion of very critical Lumding-Badarpur-Silchar line was under way. During this tenure, he planned and ensured unhindered supply of food grains and essentials to far off states like Tripura, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland and Lower Assam.

Shri Malkhede has worked on Central Railway in various positions across Operations & Commercial departments and General administration. He has worked as Senior Divisional Commercial Manager, Mumbai Division, Deputy Chief Operations Manager (Freight), Deputy General Manager (Gen), Deputy Chief Vigilance Officer (Traffic) and other positions. He has worked on deputation at IRCTC during the years 2015 to 2019, heading the West Zone as Group General Manager. He has also been on deputation to CONCOR during 1999-2004, when he set up Inland Container Depot (ICD) at Chhatrapati Sambhajinagar (Aurangabad) and also headed ICD Nagpur.

Shri Arvind Malkhede is a Mechanical Engineer and is a Chevening Gurukul Scholar. During the year 2009, he has studied Leadership and Management programme at prestigious London School of Economics and Political Science (LSE) and got exposure to international institutions in Europe. He has also undergone various trainings and programmes at INSEAD, Singapore ICLIF Malaysia, in Hongkong, Germany etc.



BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM (BESS) INAUGURATED IN BLUE LINE

THIS SYSTEM TO BE USED AS BACK UP POWER TO HAUL METRO TRAINS FROM THE MID SECTION IN CASE OF SUDDEN POWER CUT OR GRID FAILURE

Source/RSB- Metro Railway, Kolkata, India's first Metro, has achieved another feat by commissioning Battery Energy Storage System (BESS) at Central Metro station of Blue Line on 25.02.2026. This BESS, the first of its kind in Indian Railways and in the eastern part of our country was commissioned in presence of Shri S.S.

Mishra, General Manager and other senior officers of Metro Railway, President and other members of MRWWO. This system comprises of inverters and Advanced Chemistry Cell (ACC) Batteries, is capable of providing stored power in case of a power outage or grid failure. This 4 MW BESS is conceptualized, as per the National Programme on Advanced Chemistry Cell Battery Storage, approved by the Union Cabinet in the year 2021, is powered by 6.4 MWh Lithium Iron Phosphate (LFP) battery as energy storage element.

This new system has been designed in such a way that the electricity stored by it can be used to haul rakes at 55 km/hr speed from the mid-tunnel to the next



station, if stranded in case of any Grid Failure besides providing power supply to tunnel ventilation and environment control system at the underground stations. This system also equipped with green batteries has lifespan of around 14 years and very compact in design. It is also going to reduce carbon footprint with better energy efficiency than conventional Generators.

It will efficiently handle spikes in power demand and improve power factor which will reduce energy bill.



Shri V. Somanna Inaugurates Pedestrian Subway at Shettihalli, lays Foundation Stone for FOB at Kyatsandra, Reviews key Railway Projects in Tumakuru District

Source/RSB- Shri V. Somanna, Hon'ble Minister of State for Railways, inaugurated a newly constructed pedestrian subway at Shettihalli in Tumakuru district and laid the foundation stone for a new Foot Over Bridge (FOB) at Kyatsandra railway station.

Addressing the gathering, he said that the new pedestrian subway will allow local residents to cross the railway tracks safely and conveniently. He also mentioned that Tumakuru is developing rapidly, and railway facilities must be upgraded to meet the growing demands of passengers. The Minister also stated that the land acquisition is progressing well for the new railway lines between Tumakuru– Davanagere and Tumakuru–Rayadurga. Train services between Chitradurga and Davanagere are expected to commence shortly. He emphasized that long-pending railway projects are now being given priority. Across Karnataka, railway works worth about ₹52,000 crore are in progress, with special focus on construction of Road Over Bridges (ROBs) and Road Under Bridges (RUBs) to improve safety and ease traffic congestion. Shri Suresh Gowda, MLA, Tumakuru Rural, said that the Tumakuru– Davanagere and Tumakuru–Rayadurga railway projects are progressing steadily and are expected to be completed soon. Shri G.B. Jyothi Ganesh, MLA, Tumakuru City, appreciated the fast pace of railway works and thanked the government for speeding up development in the region.



Shri Praveen Kataraki, Additional Divisional Railway Manager (ADRM), Bengaluru Division, informed that the Bengaluru City–Sampige Road section has 25 level crossings. Most have been sanctioned for ROBs and RUBs. So far, five RUBs have been completed, two are under progress, and 11 ROBs are being taken up, involving works worth around ₹1,500 crore in this section. The Minister also inspected ongoing ROB works at Mallasandra Gate and Heggere Gate (₹21.32 crore), reviewed the RUB at Bheemsandra (₹1.87 crore), and examined ROB works at Baddihalli Gate (₹17.38 crore), Batwadi Gate (₹43.37 crore), Mydala Gate (₹40.60 crore), and Panditanahalli Gate. Shri G.B. Jyothi Ganesh, MLA, Tumakuru City; Shri Suresh Gowda, MLA, Tumakuru Rural; Shri Praveen Kataraki, ADRM, Bengaluru Division; and other railway officials were present on the occasion.

RailTel Successfully Curates AI Healthcare Panel Discussions at AI Impact Summit 2026

RailTel, a key enabler in building secure, scalable, and resilient digital infrastructure, can power AI-driven public health services: Shri Sanjai Kumar, CMD, Railtel



Source/RCIL- RailTel Corporation of India Ltd., a Navratna CPSE under the Ministry of Railways, successfully curated and hosted two important panel discussions on Artificial Intelligence–driven healthcare at the AI Impact Summit 2026, held at Bharat Mandapam. The mega summit was organized under the aegis of the Ministry of Electronics and Information Technology and the IndiaAI Mission, bringing together policymakers, technology leaders, healthcare professionals, researchers, and innovators from India and across the globe. RailTel curated two focused sessions titled “Public Health Powered by AI: RailTel’s Collaborative Model for AI-enabled Inclusive Healthcare for Bharat and Beyond” and “AI for Inclusive, Accessible, and Universal Healthcare.” Both sessions witnessed engaging discussions on leveraging Artificial Intelligence to strengthen public health systems, enhance healthcare accessibility, and ensure inclusive and equitable healthcare delivery.

The panel discussion on “Public Health Powered by AI” emphasized the importance of collaborative models involving government institutions, healthcare providers, research organizations, and technology partners. Panellists highlighted AI’s potential to strengthen disease surveillance, enable early detection, enhance clinical decision support, and improve population-scale health management. It was also stressed that AI must be developed and deployed as a catalyst for equity, ensuring it helps bridge healthcare gaps rather than widen existing disparities.

The second session on “AI for Inclusive, Accessible, and Universal Healthcare” focused on ensuring that AI-driven healthcare solutions reach underserved & remote populations. Experts underscored the need for patient-centric government policies, noting that healthcare innovation cannot be driven solely by profitability. The discussion highlighted key challenges such as limited high-bandwidth infrastructure in remote regions, the need for realistic deployment expectations aligned with on-ground realities, and the importance of measuring meaningful outcome-based indicators to assess AI’s impact. Panellists also emphasized that improving healthcare literacy is essential to prevent confusion and ensure AI supports truly universal and inclusive healthcare delivery.

The sessions featured distinguished panellists and moderators from government, healthcare institutions, academia, and industry, whose insights helped translate AI’s potential into actionable strategies for real-world implementation.

Talking about the sessions Shri Sanjai Kumar, CMD/RailTel said “We express our sincere gratitude to MeitY and the IndiaAI Mission for entrusting RailTel with the responsibility of organizing these important panel discussions at the India AI Impact Summit 2026. This summit provided a valuable platform to deliberate on how Artificial Intelligence can drive inclusive and accessible healthcare for Bharat and beyond. As a public sector enterprise committed to supporting national digital initiatives, RailTel sees itself as a key enabler in building secure, scalable, and resilient digital infrastructure that can power AI-driven public health services.”



RVNL and Texmaco Rail & Engineering Ltd. signed a Shareholders’ Agreement in New Delhi to form a new JV company.

Source/RVNL- Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) and Texmaco Rail & Engineering Ltd. have signed a Shareholders’ Agreement in New Delhi to establish a new joint venture company aimed at tapping integrated rail rolling stock and infrastructure opportunities in India & international markets. The proposed JV will focus on delivering comprehensive rail solutions, including rolling stock and allied infrastructure projects, across India as well as in key overseas regions such as Asia, Africa, and the Middle East. The collaboration is expected to combine RVNL’s project execution expertise with Texmaco’s manufacturing and engineering capabilities to address emerging demands in the rail sector. The agreement was signed in the presence of Shri Saleem Ahmad, Chairman and Managing Director, RVNL; Shri Manish Agarwal, PED (Mechanical); and Shri Ajit Singh, PED (Corporate Coordination & Business Development). Representing Texmaco were Shri Saroj Kumar Poddar, Chairman, Adventz Group, and Shri Sudipta Mukherjee, Managing Director, Texmaco Rail & Engineering Ltd.



RITES & SAIL sign MoU for loco leasing and maintenance services



Source/RITES PR - RITES Limited, the leading Transport Infrastructure Consultancy and Engineering firm signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Steel Authority of India Limited (SAIL), a CPSE under the Ministry of Steel, Government of India. The MoU provides a framework for collaboration to support SAIL’s plants and mines through specialised railway services, including wet leasing of locomotives and higher schedule maintenance of SAIL-owned diesel-electric locomotives. Under the MoU, RITES will leverage its expertise to provide locomotive leasing with operation and maintenance (O&M) support, along with higher schedule maintenance of diesel-electric locomotives. The collaboration aims at enhancing efficiency, reliability, and safety of SAIL’s in-house railway systems, while enabling SAIL to focus on its core steel production operations. With extensive experience in railway operations, maintenance, and locomotive leasing, RITES has been supporting SAIL plants for over two decades. The MoU formalises a long-term engagement to strengthen rail-based logistics critical to SAIL’s expanding steel production capacity.

CONCOR Signs MoU with Vizhinjam International Seaport Limited for Strategic Logistics Collaboration

Source/Concor- Enhancing India’s ported logistics ecosystem, CONCOR has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Vizhinjam International Seaport Limited (VISL) on 23rd February 2026 at Thiruvananthapuram for development of a Container Freight Station (CFS) in the vicinity of Vizhinjam International Seaport Thiruvananthapuram Kerala.



The MoU was signed in the august presence of Shri Pinarayi Vijayan Hon’ble Chief Minister of Kerala, Shri V. N. Vasavan Hon’ble Minister for Cooperation & Ports Government of Kerala, Shri Kowsigan (IAS) Secretary -Shipping & Ports Govt of Kerala, Shri Sanjay Swarup CMD CONCOR and Ms G. Gayatri Area Head (South) CONCOR.

The agreement was signed by Mr. A. Vijuvin Cluster Head Chennai on behalf of CONCOR and Ms Divya Iyer MD VISL on behalf of VISL. This new initiative is expected to enhance hinterland connectivity and enable seamless end-to-end services to the customers.

Northeast Frontier Railway Achieves Major Milestone in Food Safety Standards

Source/NFR- In a significant achievement towards ensuring safe and hygienic food for passengers, Dimapur Railway Station under Lumding Division of Northeast Frontier Railway has been awarded the prestigious “Eat Right Station” certification by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). The station has qualified as per the guidelines established by FSSAI and has been granted this certification for the period from 24th October 2025 to 23rd October 2027.

This recognition has been conferred after a comprehensive audit of food stalls, catering units and food handlers at the station to ensure compliance with stringent food safety standards, hygienic food preparation, safe storage practices, proper waste management and availability of nutritious food options for passengers.

In another proud achievement, four stations under Alipurduar (APDJ) Division of Northeast Frontier Railway have also been awarded the “Eat Right Station” certification by FSSAI for meeting the prescribed food safety and hygiene benchmarks. These stations are Alipurduar Railway Station, Kokrajhar Railway Station, Golakganj Railway Station and New Mal Junction Railway Station.

The certification reflects the dedicated efforts of railway officials, health inspectors, catering units, authorized vendors & station management teams who have worked in close coordination to maintain high standards of cleanliness and food safety.

The “Eat Right Station” initiative is part of FSSAI’s nationwide movement to promote safe, healthy and sustainable food practices under the “Eat Right India” campaign. Northeast Frontier Railway remains committed to continuously improving passenger amenities and ensuring that quality, safe and hygienic food is made available across all its stations.

Indian Railways' Multi-Layered Shield for the Woman Traveller

In its steadfast commitment to women's empowerment, Indian Railways reaffirms its mission to provide a secure, dignified, and inclusive travel experience for women across the nation. Through a series of dedicated operations and infrastructure projects, the railways have transitioned from being just a mode of transport to a supportive environment that prioritizes the unique needs of female passengers. From the specialized "Meri Saheli" initiative ensuring the safety of solo travelers to the "Project Ayushman" enhancing maternal comfort, these efforts reflect a holistic approach to passenger welfare. By blending modern technology with human compassion, Indian Railways continues to set new benchmarks in public service, ensuring every woman's journey is defined by safety, privacy, and respect.

Meri Saheli: A Dedicated Shield for Solo Travelers



Active across the entire Indian Railways network, the Meri Saheli initiative remains a cornerstone of passenger security. This proactive program specifically aims to provide a shield of safety to lady passengers who are traveling alone or with minors on long-distance trains. By maintaining a point of contact from the station of origin to the destination, the initiative ensures that women feel protected throughout their entire journey, fostering a sense of confidence and security while traveling across the vast railway grid during their transit.

Project Ayushman: Elevating Maternal Privacy and Comfort



Under the visionary Project Ayushman, South Western Railway provides a first-of-its-kind nursing room facility at the historic Mysuru Railway Station. Located conveniently on Platform 2, this dedicated space offers a quiet, hygienic, and secure environment for nursing mothers and their infants. Developed in collaboration with Ladies Circle India, this facility blends comfort with compassion, bringing a new level of dignity and privacy to traveling mothers who previously struggled to find appropriate spaces for childcare while navigating the busy station environment.



Operation Matrishakti: Assisting Expectant Mothers in Transit

Going far beyond the standard call of duty, RPF personnel & particularly women officers demonstrate exceptional compassion through Operation Matrishakti. This initiative is dedicated to assisting pregnant women who unexpectedly go into labor during their train journeys. These officers provide critical medical support and care in high-pressure situations, ensuring that both mother and child are safe. It is a heartening example of how the railway staff serves as a lifeline for families in transit during their most vulnerable and critical moments.

Shishu Aahar Kaksh: Expanding Baby Feeding Rooms

The provision of "Shishu Aahar Kaksh" (Baby Feeding Rooms) is a continuous and evolving mission across Indian Railways. Currently, these specialized facilities are operational at approximately 450 stations nationwide, with plans for further expansion based on passenger volume and local requirements. To ensure a premium experience, the railways conduct periodic inspections and maintain strict cleanliness standards, ensuring that these rooms remain a comfortable and safe sanctuary for mothers and infants throughout their travels across the country.



Ladies Special Trains: Vigilant Security in Every Coach



Security for women is further bolstered by the presence of lady RPF personnel who actively escort Ladies Special trains in metropolitan cities. In other trains where escorts are provided, the personnel are briefed to maintain an extra vigil on ladies' coaches and women traveling alone. This heightened surveillance at halting stations and en-route ensures that potential threats are deterred and that female passengers have immediate access to assistance, ensuring a peaceful and protected transit environment for all women using the rail network.

Exclusive Waiting Rooms: A Private Space for women



Infrastructure development remains a top priority, with the continued maintenance of dedicated Ladies' Waiting Rooms at all major railway stations. These rooms provide a private and secure area for women to rest and wait for their departures away from the general crowd. The project is currently ongoing, with continuous upgrades being implemented to improve amenities and capacity, reflecting the railways' long-term dedication to creating a gender-sensitive infrastructure that meets the evolving needs of female travelers nationwide.

Hon'ble PM inaugurated balance sections of Namo Bharat corridor & Meerut Metro

Source/NCRTC- The Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, inaugurated the balance sections of the Delhi-Meerut Namo Bharat corridor, Sarai Kale Khan to New Ashok Nagar and Meerut South to Modipuram, and the Meerut Metro from Meerut, describing the project as a new surge of energy for a 'Viksit Uttar Pradesh' and a 'Viksit Bharat'. This event marks the first time in India that both a rapid rail and a metro service will operate on the same infrastructure. During his visit, the Prime Minister travelled on Meerut Metro and interacted with students and passengers. The Prime Minister lauded the project as a symbol of 'Nari-Shakti,' noting that most train



operators and station control staff are women. He congratulated the people of Uttar Pradesh on the country's first Namo Bharat Rapid Rail service. The event was broadcast live at Sarai Kale Khan station in Delhi, where a ceremony was held with Hon'ble Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Shri Manohar Lal, as the Chief Guest. Delhi Lieutenant Governor Shri Vinay Kumar Saxena, Union Minister of State for Road Transport and Highways Shri Harsh Malhotra, and Delhi Government Minister Shri Ashish Sood were also present. The dignitaries watched the live broadcast of the Prime Minister's inauguration and his address to the public gathering.

7th All India Conference of Government Railway Police Chiefs Held at Vigyan Bhawan

Conference Aimed at Strengthening Passenger and Railway Infrastructure Security, with Focus on Coordinated Operations, Speedy FIR Registration and Advanced Surveillance Technologies

Special Emphasis on Prevention of Narcotics and Drug Trafficking Through Proactive Surveillance and Real-Time Intelligence Sharing

Source/RSB-The 7th All India Conference of Government Railway Police Chiefs, convened by the Railway Protection Force concluded successfully at Vigyan Bhawan, New Delhi. The high-level conference, presided over by Director General, RPF, Ms Sonali Mishra, witnessed the participation of DGPs, ADGPs, and senior officers from the GRP of various states and union territories. The conference was graced by the presence of Chairman-cum-CEO, Railway Board, Shri Satish Kumar as well as Members of the Railway Board.

Comprehensive and constructive discussions were held to formulate a coordinated programme of action and procedural framework aimed at strengthening the security of passengers and railway infrastructure. Deliberations also focused on improving basic infrastructure facilities for GRP personnel. Emphasis was laid on fostering close coordination and joint efforts to effectively address the issues discussed during the Conference.

The conference was organized to deliberate on measures for enhancing the security of passengers, railway infrastructure and operations, in view of emerging security challenges. The deliberations recognized that Indian railway, due to its vast geographical spread, high passenger footfall, and open-access architecture, remains vulnerable to a wide range of threats including organized crime, trafficking of narcotics, vandalism, stone pelting, and potential acts of sabotage. The conference aimed to develop a holistic security framework combining technology, intelligence, field coordination, and community engagement.

The conference emphasized leveraging modern



technology like FRS based CCTV cameras, AI-enabled video analytics and drone surveillance. The DG/RPF highlighted the new technological tools that are being adopted by RPF in its field operations for better identification of criminals and detection of crime.

One of the major highlights of the conference was the deliberation and formulation of a roadmap to curb the menace of drug trafficking as the railway network is vulnerable for the transport of drugs and narcotic substances. A presentation was given by a senior officer of NCB (Narcotics Control Bureau) which highlighted the importance of pro-active surveillance and real time intelligence sharing in busting gangs involved in drug trafficking.

Regular mock drills were emphasized as essential for preparedness and coordinated response during

emergencies. Scenario-based training modules focusing on first response, evacuation, crowd control, and incident management were recommended. The menace of stone-pelting and sabotage were also discussed at length as they affected passenger safety and railway operations. DG RPF emphasized the importance of community outreach and awareness programs in vulnerable localities and strict legal action and deterrent measures against offenders.

The conference served as a significant step towards reinforcing the security architecture of the Indian Railways. It provided a common platform for State Police Forces and the RPF to align their strategies, share operational experiences, and commit to a coordinated approach for safeguarding railway infrastructure and ensuring the safety and security of passengers. The outcomes of the conference are expected to contribute to a more resilient, responsive, and technology-enabled railway security system.



Delhi Metro Goes Smart: AI Now Powering Daily Operations

Source/DMRC- The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) is actively using Artificial Intelligence (AI) to enhance its operational efficiency, passenger safety, security, and overall service quality. The details of these AI-driven initiatives taken by DMRC are also on display at the AI Impact Summit at Bharat Mandapam. The Hon'ble Union Minister for Housing & Urban Affairs and Power, Sh. Manohar Lal also visited DMRC's stall and appreciated the initiatives taken towards implementing AI.

The following AI-based measures have been adopted by DMRC:

CONVERSATIONAL AGENTIC AI INNOVATION: Ask CHETNA

The DMRC CHETNA (Chatbot for Efficient Travel & Navigation Assistance) of DMRC is built on a BharatGPT-powered Agentic AI stack with a Sovereign AI architecture, enabling secure, India-hosted intelligence for metro passenger services. The solution provides interactive journey planning, fare information, real-time service updates, and ticket booking options across web and mobile platforms.

EMPOWERING THE COMPLAINT MANAGEMENT SYSTEM WITH AI

As part of its digital modernization, DMRC has introduced a state-of-the-art Complaint Management System to enhance passenger grievance redressal. This is being gradually upgraded to an Agentic AI-based system. The ongoing Phase 1 focuses on AI-enabled automation of written complaints, reducing Average Handling Time (AHT) and improving workflow transparency. In Phase 2, it will deploy an AI-powered Voice Bot on Helpline 155370 for real-time intent recognition and automated complaint registration, with seamless human escalation for complex cases.

AI BASED SYSTEMS INTRODUCED FOR OVERHEAD WIRE HEALTH MONITORING

DMRC has introduced advanced Artificial Intelligence (AI)-based systems to monitor the



health of its Overhead Equipment (OHE) network. As part of this initiative, DMRC has deployed an Overhead Wire System Health Monitoring solution using the Pantograph Collision Detection System (PCDS) on the Red Line (Line 1), Yellow Line (Line 2), Blue Line (Line 3/4). This system uses accelerometers and drop-off sensors installed on train pantographs to continuously monitor the contact between the moving pantograph and the stationary overhead wire. This helps in identifying wire alignment issues and hard points in the system.

In addition, DMRC has introduced AI-based video monitoring of the Overhead Wire network on Pink Line (Line 7) and Magenta Line (Line 8). This system analyzes video footage captured from trains using AI image analytics to detect and classify anomalies.

AI-DRIVEN TECHNOLOGIES STRENGTHEN TRAIN, TRACK SAFETY AND AUTOMATIC WHEEL PROFILE MONITORING SYSTEM

An Automatic Wheel Profile Monitoring System has been introduced on Pink Line (Line 7) to continuously check the condition of train wheels. The system uses high-precision laser sensors to scan wheel profiles while trains are moving. To enhance the train safety, an Automatic Axle Bearing Temperature Monitoring System has also been deployed on Pink Line (Line 7) and Magenta Line (Line 8).

DMRC INTRODUCES PREDICTIVE MAINTENANCE FOR TRACK CIRCUITS

DMRC has also introduced an AI-based predictive maintenance system for track circuits on its Green Line (Line 5) and Violet Line (Line 6) to reduce train delays and significantly reduce on-track maintenance interventions. The predictive maintenance system is expected to enhance service reliability, reduce emergency on-track interventions, optimise manpower deployment, and ensure smoother and safer metro operations for passengers.